# घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 43- शनिवार 13- दिसम्बर 2025,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2023-2025



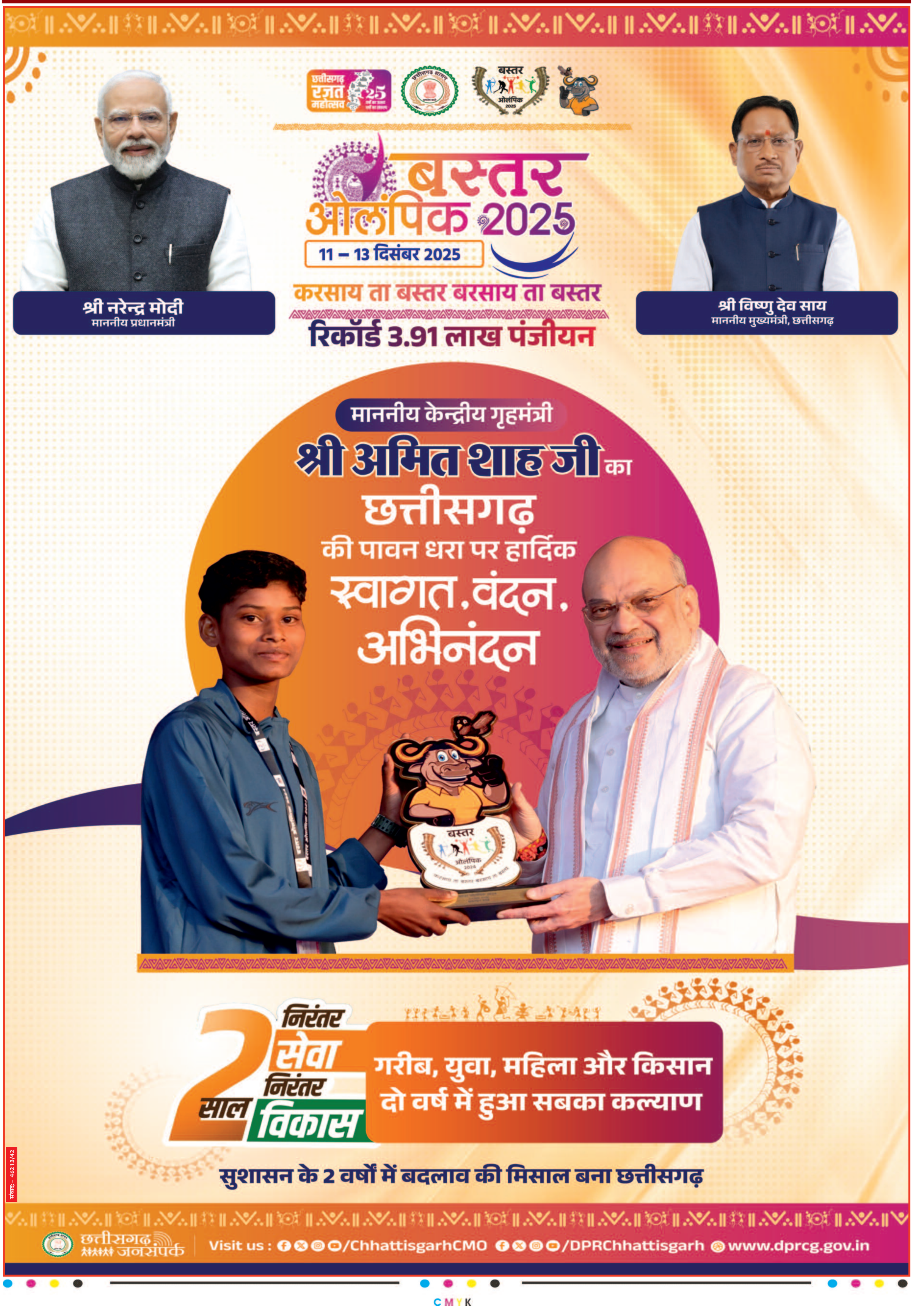

## संपादकीय

# कर्नाटक में हेट स्पीच पर नया बिल

### कठोर कानून से कम होंगे मामले पर दुरुपयोग की आशंका भी

*कर्नाटक विधानसभा में हेट स्पीच और हेट क्राइम के खिलाफ कड़े प्रावधानों वाला बिल पेश किया गया है। इसका उद्देश्य समाज में वैमनस्य फैलाने वाले बयानों और अपराधों को नियंत्रित करना है, लेकिन इसके दुरुपयोग की आशंका भी जताई जा रही है*

कर्नाटक विधानसभा में हेट स्पीच और हेट क्राइम के खिलाफ बिल पेश किया गया है। इसका मकसद है नफरत और घृणा फैलाने वाले अपराधों व बयानों को नियंत्रित करना। अक्सर कई ऐसे बयान आते रहते हैं, जिससे समाज में वैमनस्य बढ़ता है। इसे देखते हुए ऐसे कानून जरूरी लगते हैं, लेकिन इसके साथ चिंता भी है...दुरुपयोग की।

बिल के प्रावधान बेहद कड़े हैं। पहली गलती पर एक से 7 साल की सजा और दोबारा गलती होने पर 2 से 10 साल की सजा मिल सकती है। साथ में, जुर्माना भी है। विधेयक में हेट क्राइम और हेट स्पीच को विस्तृत रूप से परिभाषित किया गया है और इसका दायरा बहुत बड़ा है, जिसमें सार्वजनिक बयानबाजी से लेकर ऑनलाइन निगरानी तक शामिल है।

इसमें शक नहीं कि नफरत फैलाने वाले बयान और कृत्य इस समय की एक बड़ी परेशानी हैं,जिनसे कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती खड़ी हो जाती है। सामाजिक सद्भाव को भी चोट पहुंचती है। सुप्रीम कोर्ट कई मौकों पर इस बारे में चिंता जता चुका है। 2018 में शीर्ष अदालत ने हेट क्राइम की निंदा करते हुए कहा था कि नागरिकों की जान की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। उसी साल तहसीन पूनावाला जजमेंट आया, जिसमें राज्यों के लिए कई दिशा-निर्देश थे।लेकिन,जब इतना कड़ा कानून आता है,तो उसके दुरुपयोग की आशंका भी बढ़ जाती है। भले ही बिल में अपराध की विस्तृत व्याख्या की गई हो,लेकिन असल चुनौती है इसे लागू करने में। कौन-सी बात नफरत फैलाने वाली है और कहां आलोचना की गई है-इसमें समझ का थोड़ा भी अंतर बड़ा टकराव पैदा कर सकता है। इसी तरह,असहमति के अधिकार को भी सुरक्षित रखने की जरूरत है। बिल में सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लैटफॉर्म को भी शामिल किया गया है। इंटरनेट पर जिस तेजी से दुष्प्रचार और वैमनस्य बढ़ाने वाले कंटेंट बढ़े हैं,उसे देखते हुए बिल उपयोगी हो सकता है,पर यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आड़े नहीं आना चाहिए। बिल को लेकर कई आशंकाएं और राजनीतिक विरोध है। कर्नाटक बीजेपी का आरोप है कि यह बिल खास समूह को निशाना बनाने के लिए लाया जा रहा है। ऐसे में यह जरूरी है कि इस तरह का इंतजाम और निगरानी हो कि यह बिल किसी से बदला लेने का नहीं, बल्कि शांति कायम करने का टूल बने।

# पितृसत्ता की गहरी पैठ...



## महिलाओं पर हिंसा में अमीर देश भी पीछे नहीं

**-अभिषेक पाण्डेय-**

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने विकसित देशों में महिलाओं की असुरक्षा का खुलासा किया है। 2024 में 50,000 महिलाओं की हत्या उनके अंतरंग साथी या परिवार के सदस्यों ने की। घरेलू तनाव,पितृसत्तात्मक दबाव और कमजोर कानून इसके प्रमुख कारण हैं, जो महिलाओं को हिंसा का शिकार बनाते हैं।

हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने उस सच की परतें खोल दी हैं जिसे आर्थिक उन्नति की चकाचौंध में बड़ी ही सजगता से छुपा कर रखने का प्रयास किया जाता रहा है। अमूमन यह विश्वास किया जाता है कि विकसित देश महिलाओं के आत्मसम्मान और सुरक्षा को लेकर बेहद सजग हैं। परंतु यूएन की रिपोर्ट इस मिथक से पर्दा उठाती है।

संयुक्त राष्ट्र के ड्रग्स और अपराध कार्यालय व ह विमिन द्वारा हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक विकसित देशों में भी महिलाएं अपने घर में सुरक्षित नहीं हैं, चाहे बात अमेरिका की हो या फिर यूरोपीय देशों की। रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2024 में 50,000 महिलाओं और लड़कियों की उसके अंतरंग साथी या परिवार के सदस्य द्वारा हत्या कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक, इसकी वजह घरेलू तनाव, पितृसत्तात्मक दबाव, आर्थिक और भावनात्मक निर्भरता के साथ ही कई देशों में कमजोर कानून और धीमी न्याय प्रक्रिया भी है। किसी रिश्ते में हिंसा का उभरना अमूमन भावनात्मक शोषण से शुरू होता है। फिर वित्तीय शोषण और उसके बाद शारीरिक शोषण जैसे अधिक नियंत्रणकारी व्यवहारों में वह बदलता है। ऐसे में अक्सर शारीरिक शोषण की नौबत आने तक जीवन पूरी तरह उलझ चुका होता है। घर, बच्चे और वित्तीय मामले इस तरह से जुड़ जाते हैं कि इसे आसानी से छोड़ना मुश्किल हो जाता है। यह सोच दुनिया भर में गहरी पैठ बनाए हुए है कि पुरुष प्रोवाइडर (प्रदाता) होते हैं और महिलाएं उनकी संपत्ति होती हैं। इसलिए विवाहित होने पर, महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने पति की आज्ञा मानें,उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करें और समान निर्णय लेने का प्रयास न करें। यदि वे इन मानदंडों का उल्लंघन करती हैं,तो दंड के तौर पर उन्हें शारीरिक हिंसा झेलनी पड़ सकती है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा को अमूमन या तो व्यक्तिगत मुद्दा करार दिया जाता है या कुछ बुरे पुरुषों के व्यवहार के रूप में देखा जाता है। हालांकि यह एक व्यापक, सामूहिक, सामाजिक समस्या है,जिसकी जड़ें मर्दानगी को केंद्र में रखकर बनाए गए सामाजिक मानदंडों में निहित हैं। सामाजिक रूप से निर्मित ये धारणाएं महिलाओं का ही व्यवहार निश्चित नहीं करतीं, ये पुरुषों को भी कथित मर्दाने स्वभाव को अपनाने के लिए बचपन से ही तैयार करती हैं। जहरीली मर्दानगी की यह पाठशाला निरंतर इस तथ्य को स्थापित करती रहती है कि स्त्रियों पर नियंत्रण के लिए शारीरिक दंड आवश्यक है। मर्दानगी की इन सामाजिक कसौटियों पर खरा उतरने का दबाव लड़कों और पुरुषों पर होता है और यह हिंसात्मक व्यवहार को कम नहीं होने देता चाहे विकास की कितनी ही इबारतें लिखी जाएं।

# आज भारतीय लाइब्रेरियन कई तरह के डिजिटल दक्षताओं के बिना आगे नहीं बढ़ सकता



**डॉ विजय गर्ग**
मलोट,पंजाब

एक समय था,जब लाइब्रेरियन का काम केवल किताबों की अलमारियों में किताबों को व्यवस्थित रखना,कैटलॉग तैयार करना और पाठकों को आवश्यक पुस्तक तक पहुंचानाभर समझा जाता था। लेकिन पिछले एक दशक में भारत में जो डिजिटल क्रांति हुई है,उसके चलते अब लाइब्रेरियनशिप एक पारंपरिक सेवा से बदलकर अत्यंत आधुनिक,टेक संचालित और रणनीतिक कैरियर बन चुका है। आज लाइब्रेरियन सिर्फ पुस्तकों के संरक्षक नहीं बल्कि डिजिटल नॉलेज मैनेजर हैं। इन्हें डाटा क्यूरेटर,लर्निंग टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट और इंफार्मेशन नेविगेटर भी कह सकते हैं। वास्तव में भारत सरकार की राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी पहल ने विश्वविद्यालयों में ई-रिसोर्सेज़ की उपलब्धता,ऑनलाइन जर्नल की सदस्यता और ई-गवर्नेंस ने लाइब्रेरियन की भूमिका को पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट और वर्सेटाइल बना दिया है। लाइब्रेरियन केवल भौतिक पुस्तकों को ही नहीं बल्कि ई-बुक,ई-जर्नल, डेटा बेस,ओपन सोर्स रिपॉजिटरी, डिजिटल आर्काइव्स आदि का भी संचालन करता है। इसलिए आज के लाइब्रेरियन के पास डिजिटल रिपॉजिटरी मैनेजमेंट, डेटा माइग्रेशन, मेटा डेटा स्कीम और क्लाउड आधारित लाइब्रेरी सिस्टम, जिनमें कौशल होना आवश्यक है। ऐसे

*लाइब्रेरियन अब सिर्फ पुस्तकों के संरक्षक नहीं उनका पेशा अब आधुनिक टेक संचालित हो चुका है। ई-रिसोर्सेज़ की उपलब्धता,ऑनलाइन जर्नल की सदस्यता और ई-गवर्नेंस ने उसकी भूमिका स्मार्ट और वर्सेटाइल बना दी। वह अब स्कूल,कॉलेज तक सीमित नहीं बल्कि कंपनियों के नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में लाइब्रेरियन की डिजिटल दक्षता,डेटा इंडेक्सिंग,कंटेंट क्यूरेशन, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट आदि काम आती हैं।*

ज्ञान से लैस पेशेवरों की मांग विश्वविद्यालयों, सरकारी संस्थानों, शोध केंद्रों और कार्पोरेट सेक्टर में बहुत तेजी से बड़ी है।

### ऑटोमेशन और एआई का असर

आधुनिक लाइब्रेरी अब आईएलएस (इंटीग्रेटिड लाइब्रेरी सिस्टम) आरएफआईडी,एआई आधारित सर्च सिस्टम और ऑटोमेटिक कैटलॉगिंग का उपयोग करती है। इस बदलाव के कारण लाइब्रेरियन अब केवल रिकॉर्ड दर्ज करने वाले व्यक्तिभर नहीं हैं बल्कि एआई फ्रेंडली,नॉलेज आर्किटेक्ट बन गये हैं। आज की दुनिया में इनका काम नये-नये आयाम हासिल कर चुका है। मसलन-ऑटोमेशन सिस्टम सेटअप करना,डेटा की सटीकता और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना,उपयोगकर्ताओं को डिजिटल लर्निंग गाइडेंस देना,खोज परिणामों को बेहतर बनाने के लिए एआई टूल्स के पैरामीटर्स को समझना, इन तमाम तकनीकों ने लाइब्रेरियन के कार्यक्षेत्र को बढ़ाया है।

### डिजिटल स्किल्स ने खोले नये रोजगार क्षेत्र

डिजिटल कुशल लाइब्रेरियन अब केवल स्कूल,कॉलेज तक सीमित नहीं बल्कि कई कंपनियां अब नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम चलाती हैं। यहां लाइब्रेरियन डिजिटल दक्षता,डेटा इंडेक्सिंग,कंटेंट क्यूरेशन,डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट आदि बहुत काम आती हैं। लाइब्रेरियन आज ई-लर्निंग कंटेंट स्पेशलिस्ट बन चुके हैं। वो ऑनलाइन शिक्षा,एलएमएस प्लेटफॉर्म आदि के बढ़ने से कंटेंट टैगिंग,डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेस की मैपिंग और यूजर बिहेवियर एनालिसिस आदि का भी काम करते हैं। आजकल लाइब्रेरियन को डिजिटल आर्किविस्ट भी कहा जाता है। ये अखबारों,सरकारी दफ्तरों और संग्रहालयों आदि में महत्वपूर्ण दस्तावेजों को डिजिटाइज करने का काम करते हैं। यहां लाइब्रेरियन की मेटा डेटा और डॉक्यूमेंट पिजर्वेशन स्कीम काम आती है। रिसर्च डेटा मैनेजर जैसी पोस्ट भी आजकल लाइब्रेरियन को मिल रही हैं,जिससे वो शोध संस्थानों में डेटा संग्रह, वर्गीकरण, सांख्यिकीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखना और ओपन एक्सेस नीतियों का पालन कराते हैं।

### शिक्षण सहायक भी

नई शिक्षा नीति 2020 के बाद उच्च शिक्षा संस्थानों में लाइब्रेरियन छात्रों को डिजिटल साक्षरता,रिसर्च मेथ्डोलॉजी, प्लेजरिज्म अवेयरनेस और डेटा बेस नेविगेशन जैसे विषयों पर मुख्य मार्गदर्शक बनकर उभरे हैं। ये परिवर्तन लाइब्रेरियन को शिक्षा व्यवस्था का सक्रिय सहयोगी बनाते हैं। इससे लाइब्रेरियन की प्रतिष्ठा और भूमिका दोनों मजबूत हुई हैं। डिजिटल इंडिया और स्मार्ट लाइब्रेरी के इस नये युग में स्मार्ट सिटी मिशन,डिजिटल ग्राम लाइब्रेरी आदि के बढ़ने से लाइब्रेरियन के रोजगार में क्षेत्रीय विस्तार हुआ है।



ग्रामीण और शहरी दोनों स्तरों पर लाइब्रेरियन का रूप बदल गया है। आईटी आधारित,सेल्फ चेक इन/आउट स्टेशन, क्लाउड कैटलॉग और मोबाइल ऐप- बेस्ड लाइब्रेरी सेवाएं-ये सब डिजिटल दक्षता की वजह से संभव हुआ है।

### कौशल और तकनीक का संगम

आज भारतीय लाइब्रेरियन कई तरह के डिजिटल दक्षताओं के बिना आगे नहीं बे सकता। मसलन कोहा, डी-स्पेस, ई-ग्रंथालय जैसे सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है। मसलन-मेटा डेटा की विशेषज्ञता,डिजिटल प्रिजर्वेशन,वेब डिजाइन की समझ,साइबर सुरक्षा और गोपनीयता व कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का संचालन। ये कुशलताएं आज लाइब्रेरियन में होनी ही चाहिए। लाइब्रेरियन का वेतन भी अब पहले से बेहतर हुआ है। सरकारी विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थान 45 हजार से 1 लाख 20 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन देते हैं। कारपोरेट सेक्टर में यह 60 हजार से 1 लाख 50 हजार रुपये प्रतिमाह हो सकता है। डिजिटल आर्किविस्ट/कंटेंट क्यूरेटर को 40 हजार से 1 लाख रुपये प्रतिमाह और रिसर्च डेटा मैनेजर को 70 से 1 लाख 40 हजार रुपये तक का प्रतिमाह वेतन आसानी से मिल जाता है। इस तरह डिजिटल तकनीक ने लाइब्रेरियन का प्रोफेशन विकसित, प्रतिष्ठित और बहुआयामी बना दिया है।

# जब इलाज भी बाजार बन जाए

**भारत में बढ़ती निजीकरण प्रवृत्ति और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय की कमी,क्या 'स्वास्थ्य का अधिकार' सच में न्यायालयों में लागू किया जा सकता है? जब उपचार एक सेवा नहीं,बल्कि बाज़ार की वस्तु बन जाए,तब अधिकारों की भाषा कमजोर पड़ जाती है।**

**डॉ. सत्यवान सौरभ,**
बड़वा,सिवानी,भिवानी, हरियाणा

## भारत में स्वास्थ्य अधिकार की लड़ाई



भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा और ढांचा तेजी से बदल रहा है। चिकित्सा उपचार,जो कभी सार्वजनिक दायित्व और कल्याणकारी राज्य की बुनियादी जिम्मेदारी माना जाता था,अब अधिकाधिक निजी क्षेत्र के हाथों में जाता दिख रहा है। एक ओर, सरकारी स्वास्थ्य ढांचा सीमित बजट,कम मानव संसाधन और कमजोर बुनियादी ढांचे से जूझता रहता है,दूसरी ओर,निजी अस्पतालों और कॉर्पोरेट मेडिकल चेन की पहुंच और प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। इन दोनों के बीच आम नागरिक,विशेषकर गरीब, ग्रामीण, दलित,आदिवासी,अल्पसंख्यक और हाशिए पर रहने वाले समुदाय, स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती लागत और असमान पहुंच के बोझ तले दबते जा रहे हैं। इसी बदलते परिदृश्य में,भारत में यह बहस और तेज़ हो गई है कि क्या स्वास्थ्य को एक न्याय संगत और लागू करने योग्य मौलिक अधिकार बनाया जाए। क्या न्यायपालिका इस अधिकार को इनफोर्स करा सकेगी,जब व्यवस्था ही बुनियादी रूप से असमान, महंगी और निजीकरण-प्रधान हो चुकी हो? यह प्रश्न केवल कानूनी नहीं है,यह गहराई से राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक है। क्योंकि अधिकार तभी सार्थक होता है जब राज्य उसे प्रदान करने की सामर्थ्य और इच्छा दोनों रखता हो।

भारत में स्वास्थ्य का अधिकार अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 21 के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा मान्यता प्राप्त है, पर इसे अभी तक स्पष्ट रूप से एक स्वतंत्र मौलिक अधिकार नहीं बनाया गया है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि राज्य अभी तक ऐसी बाध्यकारी जिम्मेदारी स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है जिसमें हर नागरिक को समान, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण उपचार मिल सके। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि जब तक इसे एक इंफोर्सेअब्ले राइट नहीं बनाया जाएगा, तब तक असमानता, शोषण और मनमानी शुल्क वसूली जैसे मुद्दे निरंतर बढ़ते रहेंगे।

भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि देश विश्व की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, परंतु स्वास्थ्य पर होने वाला सार्वजनिक व्यय आज भी दुनिया के सबसे कम आंकड़ों में शामिल है। जब राज्य स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पर्याप्त बजट नहीं देता, तब स्वाभाविक रूप से रिक्त स्थान निजी क्षेत्र भरता है—और यही से उत्पन्न होती है असमानता, अनियंत्रित शुल्क, अनावश्यक चिकित्सा प्रक्रियाएँ,और आम व्यक्ति की आर्थिक तबाही।

निजीकरण के विस्तार का दूसरा पहलू यह है कि यह केवल स्वास्थ्य सुविधाओं के संचालन तक सीमित नहीं है,यह स्वास्थ्य नीति,दवाओं की कीमतों, बीमा योजनाओं और सार्वजनिक-निजी भागीदारी की दिशा को भी प्रभावित कर रहा है। जब स्वास्थ्य एक लाभ आधारित उद्योग बन जाता है, तब उपचार की प्रकृति, लागत,पहुंच और गुणवत्ता सभी बाज़ार के नियमों के अधीन हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य का अधिकार कागज़ पर तो हो सकता है, पर धरातल पर वह व्यापक रूप से लागू नहीं हो पाता।

एक और गंभीर समस्या है क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट,2010 का कमजोर क्रियान्वयन। जिन राज्यों में यह लागू भी है, वहाँ भी नियमन और पारदर्शिता बेहद कमजोर हैं। मरीज़ों से मनमाना शुल्क, अनावश्यक जाँचों की सलाह, महंगे पैकेज, और अत्यधिक दरों पर सर्जरी जैसे मुद्दे आम बात हो चुके हैं। यह स्थिति तब और जटिल हो जाती है जब मरीज़ की ओर से शिकायत या न्याय पाने की व्यवस्था बेहद कमजोर और अप्रभावी हो।

इसके साथ ही,भारत में आउट-ऑफ-पॉकेट एक्सपेंडिचर अभी भी कुल स्वास्थ्य व्यय का 40 प्रतिशत के आसपास है। यानी मरीज़ों को अपनी जेब से भारी राशि खर्च करनी पड़ती है। सरकारी बीमा योजनाओं—जैसे आयुष्मान—का उद्देश्य भले ही आर्थिक सुरक्षा देना हो, पर इनके दायरे में आने वाली प्रक्रियाएँ सीमित हैं,और निजी अस्पतालों द्वारा इनका उपयोग कई बार मनमाने ढंग से किया जाता है। बीमा आधारित मॉडल ने स्वास्थ्य खर्च की जड़ समस्या को हल नहीं किया है; बल्कि कई बार यह निजी क्षेत्र के लिए नया ग्राहक-स्रोत बन गया है।

असमानता का एक और स्तर सामाजिक बहिष्कार है। दलित,आदिवासी,मुस्लिम,महिलाएँ, ट्रांसजेंडर व्यक्ति, दिव्यांग नागरिक—इनके लिए स्वास्थ्य सेवाएँ पाने की राह और भी कठिन है। कई बार सरकारी अस्पतालों में संवेदनशीलता की कमी,भेदभाव, संचार अंतर, या संरचनात्मक बाधाएँ उन्हें गुणवत्तापूर्ण सेवा से वंचित रखती हैं। ऐसे में स्वास्थ्य का अधिकार केवल क़ानूनी भाषा भर नहीं रहना चाहिए, इसे सामाजिक न्याय की दृष्टि से समझना होगा।

स्वास्थ्य अधिकार को न्यायिक रूप से लागू करना तभी संभव है जब स्वास्थ्य प्रणाली मजबूत हो। इसके लिए सबसे पहले आवश्यक है कि सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को बढ़ाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य पर जीडीपी का कम से कम 5 प्रतिशत खर्च होना चाहिए; जबकि भारत अभी 2 प्रतिशत से भी कम खर्च करता है। प्राथमिक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत किए बिना, विशेषज्ञ डॉक्टरों, नर्सों और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाए बिना, दवाओं और जांचों को सस्ता किए बिना, और स्वास्थ्य संस्थानों में जवाबदेही मजबूत किए बिना—किसी भी अधिकार का लागू होना केवल सैद्धांतिक रहेगा।

दवाओं की ऊँची कीमतें और दवा कंपनियों का प्रभाव भारत की स्वास्थ्य असमानता का एक अन्य कारण है। लगभग 80त्न दवाएँ अभी भी मूल्य नियंत्रण से बाहर हैं। जब तक आवश्यक दवाओं पर सख्त मूल्य नियंत्रण नहीं होगा तथा जनऔषधि प्रणाली का विस्तार नहीं होगा, गरीब और मध्यमवर्गीय परिवार महंगी दवाओं के भार तले दबते रहेंगे।

साथ ही,स्वास्थ्य कर्मियों की स्थितियाँ भी इस संकट का एक महत्वपूर्ण पक्ष हैं। अस्थायी नियुक्तियाँ, कम वेतन,कार्यभार का दबाव और असुरक्षित कार्य वातावरण—ये सभी कारक चिकित्सा सेवा की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा तभी संभव है जब सरकार मानव संसाधनों में उचित निवेश करे।

इन सभी परिस्थितियों में,स्वास्थ्य का अधिकार तभी वास्तविक रूप से लागू हो सकता है,जब शासन संरचना अधिक पारदर्शी, विकेंद्रीकृत और जवाबदेह बने। समुदाय आधारित निगरानी तंत्र,जिला स्वास्थ्य समितियों की मजबूती,डिजिटल पारदर्शिता,और शिकायत निवारण के प्रभावी तंत्र यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि नागरिक अपने अधिकारों का दावा कर सकें और शासन उन्हें जवाब देने के लिए बाध्य रहे। नीतिगत परिवर्तन के साथ-साथ राजनीतिक इच्छाशक्ति भी आवश्यक है। स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार लंबी अवधि का कार्य है; परंतु इसकी शुरुआत तत्काल बजट बढ़ाने, निजी अस्पतालों को सख्त नियामक दायरे में लाने,दवाओं की कीमतें नियंत्रित करने, तथा प्राथमिक स्वास्थ्य ढाँचे को मजबूत करने से हो सकती है। यह न केवल स्वास्थ्य क्षेत्र को अधिक न्यायसंगत बनाएगा बल्कि भविष्य के लिए स्वस्थ और उत्पादक समाज की नींव भी रखेगा।

अंततः, स्वास्थ्य को न्यायिक रूप से लागू करने योग्य बनाना भारत के संवैधानिक दर्शन—विशेषकर सामाजिक न्याय—की पुनर्पुष्टि होगा। लेकिन यह तभी सम्भव है जब सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी मजबूत हो कि वह इस अधिकार को प्रत्येक नागरिक तक पहुँचाने में सक्षम हो। यदि राज्य की प्राथमिकताएँ स्वास्थ्य सुरक्षा की बजाय बाज़ार आधारित मॉडल को बढ़ावा देने में लगी रहेंगी, तो 'अधिकार' शब्द अपनी प्रासंगिकता खो देगा और नागरिकों की पीड़ा बढ़ती जाएगी।

भारत को आज यह स्वीकार करना चाहिए कि स्वास्थ्य केवल आर्थिक विकास का फल नहीं, बल्कि मानव गरिमा की बुनियाद है। और जब तक इस बुनियाद को समान रूप से मजबूत नहीं किया जाएगा, तब तक स्वास्थ्य का अधिकार कागज़ पर तो रहेगा, पर जनता के जीवन में नहीं।

# सुधर सकता है इलेक्शन सिस्टम...

**-ए.एस.पाण्डेय-**

### चुनावी व्यवस्था में बदलाव जरूरी, पर इसे भ्रष्ट बताकर नकारना गलत

भारत की चुनाव व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। क्या मतदान सिर्फ दिखावा है। बैलेट पेपर पर लौटने की मांग हो रही है। हालांकि, मौजूदा व्यवस्था को पूरी तरह खराब नहीं कहा जा सकता। इसमें सुधार की गुंजाइश है। राजनीतिक दलों और चुनाव अधिकारियों की सतर्कता व ईमानदारी से चुनावी गड़बड़ियों से बचा जा सकता है। क्या भारत में मतदान बस दिखावा है? क्या देश को बैलेट पेपर पर लौट जाना चाहिए? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। हकीकत में हर व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश होती है, पर इसका यह मतलब नहीं कि मौजूदा व्यवस्था पूरी तरह खराब है। भारत की चुनाव व्यवस्था में सुधार जरूरी है और हो सकता है, लेकिन इसे भ्रष्ट बताकर नकारा नहीं जा सकता।

भारत में जब बैलेट पेपर चलते थे, तब भी कुछ राज्यों में बूथ कैप्चरिंग और फर्जी मतदान की घटनाएं होती थीं। यहां तक कि ईव्हीएम दौर में भी कई जगह स्थानीय गुंडे बूथ में घुसकर उन लोगों के नाम पर वोट डाल देते हैं,जो वोटिंग के लिए नहीं आए होते। यह वोटिंग मशीन की नहीं,राजनीतिक विफलता है।

राहुल गांधी वोट चोरी का जो आरोप लगा रहे हैं,उसे मजाक कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। उनका आरोप है कर्नाटक में फॉर्म 7 के जरिये बड़े पैमाने पर नाम काटे गए और इसके लिए जिनकी आईडी का इस्तेमाल हुआ, उन्हें भी इसकी जानकारी नहीं थी। अब यह बात समझ से परे है कि चुनाव आयोग ने जांच को रोकने की कोशिश की और सहयोग नहीं किया।

अगर फर्जी मतदाता पंजीकृत हो रहे हैं, तो राजनीतिक पार्टियों और सामाजिक संगठनों को आपत्ति उठाने का समय मिलना चाहिए। इसके लिए उन्हें मतदाता सूची समय पर मिलनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए जिसकी मशीन से जांच हो सके। चुनाव आयोग का कहना कि यह मतदाताओं के निजता के अधिकार का उल्लंघन है,बेकार बात है। आप किसे वोट देते हैं, यह निजी मसला है, लेकिन मताधिकार सार्वजनिक है। वोटर लिस्ट इसी सार्वजनिक अधिकार का रेकॉर्ड है, इसलिए इसे गोपनीय रखने का मतलब नहीं बनता। कई बार ऐसा हुआ है कि आखिरी घंटों में वोटिंग अचानक बहुत बढ़ गई। यह वोटिंग सही भी हो सकती है और फर्जी भी। मतदान को लेकर अगर कोई शिकायत हो और मामला कोर्ट में पहुंचे, तो फैसला आने तक रेकॉर्डिंग सुरक्षित रखनी होती है। लेकिन,मान लीजिए अगर वोटिंग के 45 दिनों बाद फ्रॉड के सबूत मिलते हैं और याचिका दायर की जाती है, तो रेकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। यही नहीं,आयोग के सदस्यों को भी मनमाने तरीके से इम्युनिटी दे दी गई है। सीसीटीवी फुटेज को केवल चुनावी गड़बड़ी के संभावित सबूत के रूप में ही क्यों देखा जाए? इसे तो ऐतिहासिक दस्तावेज मानना चाहिए, जिसे भविष्य के इतिहासकार यह समझने के लिए देखेंगे कि किसी इलाके में लोकतंत्र कैसे काम करता था। यह तर्क देना कि ऐसी फुटेज का दुरुपयोग कर फर्जी विडियो बनाए जा सकते हैं, उतना ही अव्यावहारिक है जितना यह कहना कि महिलाओं को शादी-ब्याह के विडियो में न दिखाया जाए। क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं हो सकती? अगर चुनाव अधिकारी मिलीभगत करें, तो यह संभव है कि जिस एस आई आर पर मतदाताओं ने मतदान किया है, उसकी जगह दूसरी मशीन रख दी जाए। ऐसी मशीन, जिसमें पहले से मनचाहे वोट दर्ज हों। इसी तरह, मिलीभगत से यह भी संभव है कि मशीनों को ऐसे प्रोग्राम किया जाए,जिससे वो कुछ और वोट दर्ज करें, जबकि वोटर ने दबाया कुछ और हो।




चुनावी गड़बड़ियों से बचने की सबसे बड़ी ढाल है राजनीतिक दलों और उनके कार्यकर्ताओं की सतर्कता। साथ में चुनाव अधिकारियों की ईमानदारी भी जरूरी है। दुनिया में कहीं भी परफेक्ट लोकतंत्र बना-बनाया नहीं मिलता,उसे बनाना पड़ता है। स्ढ्ढक्रके दौरान विदेशी नागरिकों को हटाने के अभियान पर यह बुनियादी सिद्धांत लागू होना चाहिए कि आरोप साबित होने तक हर आरोपी निर्दोष माना जाता है। जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि वोटर लिस्ट में शामिल या आवेदन करने वाला कोई शख्स विदेशी नागरिक है, उसे मत देने का अधिकार मिलना चाहिए।




ए.पी.जे. अब्दुल कलाम

**सूचना**

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

-सम्पादक

# राष्ट्रीय एकता शिविर में शामिल हुए शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अंबिकापुर के स्वयं सेवक प्रसंजीत

-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 12 दिसम्बर 2025 (घटती-घटना)।

राष्ट्रीय सेवा योजना का राष्ट्रीय एकता शिविर 2025 दिनांक 22 नवंबर से 28 नवंबर 2025 तक सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभ विद्यानगर, गुजरात में आयोजित हुआ। राष्ट्रीय एकता शिविर का मुख्य उद्देश्य विविध पृष्ठभूमि के युवाओं को एक साथ लाकर, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय एकता व अखंडता को मजबूत करना है। यह शिविर 'सरदार @150: एक भारत. आत्मनिर्भर भारत' थीम पर आधारित रहा । उक्त प्रतिष्ठित राष्ट्रीय शिविर में शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, अम्बिकापुर से सरगुजा संभाग के एकमात्र रा.से. यो. स्वयंसेवक प्रसंजीत बनिक बी.टेक. 7th सेमेस्टर, सिविल इंजीनियरिंग, ने सहभागिता कर कॉलेज व प्रदेश का गौरव बढ़ाया । शिविर के दौरान क्षेत्रीय खेल, नुक्कड़ नाटक, रंगोली एवं पोस्टर प्रदर्शन, राज्य की सांस्कृतिक कला एवं नृत्य प्रस्तुति, यूनिट मार्च तथा राष्ट्रीय पदयात्रा, क्षेत्रीय भ्रमण के रूप में नर्मदा जिले में स्थित नर्मदा नदी के किनारे स्टैचू ऑफ यूनिटी का भ्रमण जैसे कार्यक्रमों के आयोजन किए गए, जिनमें पुरे उत्साह के साथ स्वयं सेवकों ने अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन दिया । शिविर में डॉ. अशोक कुमार श्रोती (एनएसएस - क्षेत्रीय निदेशक भोपाल), डॉ. कमल कुमार कर (एनएसएस - क्षेत्रीय निदेशक अहमदाबाद), डॉ. जागृति सुवेरा (कार्यक्रम समन्वयक, एनएसएस, सरदार पटेल विश्वविद्यालय), डॉ. निरंजन पटेल (कुलपति, सरदार पटेल विश्वविद्यालय, आनंद) डॉ. कमल कुमार कर (रीजनल डायरेक्टरेट एनएसएस, अहमदाबाद) और डॉ. भैलालभाई पी. पटेल (रजिस्ट्रार, सरदार पटेल विश्वविद्यालय) आदि अतिथि शामिल हुए और विविध विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए तथा स्वयंसेवकों को अपने आशीर्वचनों से उत्साहवर्धन एवं मार्गदर्शन दिया । CSVTU भिलाई के कुलपति डॉ. अरुण अरोड़ा. शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अम्बिकापुर के प्राचार्य डॉ. आर. एन. खरे, कार्यक्रम समन्वयक डॉ. डी. एस. रघुवंशी तथा संस्था कार्यक्रम अधिकारी ने इस उपलब्धि पर प्रतिभागी स्वयंसेवक को बधाई दी तथा उज्ज्वल भविष्य की कामना की ।

# पूर्व महापौर और पार्षदों का लंबित मानदेय भुगतान करने उच्च न्यायालय ने दिया आदेश

## कांग्रेस पार्षदों ने हाईकोर्ट में लगाई थी याचिका

-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 12 दिसम्बर 2025 (घटती-घटना)।

नगर निगम के पूर्व महापौर और पार्षदों के लंबित मानदेय को लेकर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने गाइडलाइंस जारी करते हुए इस मामले के निपटारे का आदेश जारी किया है। 2019 से 2025 की अवधि तक के निगम कार्यकाल के चुने हुए महापौर और पार्षदों का मानदेय जून 2023 से लंबित है। इस बीच जनवरी 2025 में इस अवधि के महापौर और पार्षदों के कार्यकाल भी समाप्त हो गया। मानदेय का भुगतान नहीं होने के कारण महापौर एवं कांग्रेस से जुड़े 21 पार्षदों ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया था। इसपर उच्च न्यायालय ने 28 नवंबर को आदेश जारी किया था। याचिका की बहस के दौरान नगर पालिका निगम के अधिवक्ता ने यह तर्क दिया था कि पूर्व महापौर और पार्षदों ने उन महीनों के हिसाब नहीं दिया है जिनका मानदेय नहीं दिया गया है। सभी पक्षों को सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया कि सभी पिटीशनर जिनमें पूर्व महापौर और पार्षद शामिल हैं आदेश के 2 सप्ताह के अंदर निगम अम्बिकापुर के समक्ष मानदेय नहीं मिलने वाली अवधी का हिसाब देंगे, और निगम अम्बिकापुर हिसाब प्राप्त होने के 3 माह के अंदर राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 12 मई 2022 के हिसाब से निपटारा करें। जिसपर याचिकाकर्ता महापौर और पार्षदों ने 11 दिसंबर को आयुक्त, नगर निगम अम्बिकापुर को अपने बकाया मानदेय विवरण दे दिया है।

### लगभग डेढ़ करोड़ का मानदेय है अटका

निगम अम्बिकापुर द्वारा निगम के पूर्व कार्यकाल ने जून 2023 से जनवरी 2025 तक पार्षदों और महापौर को मानदेय भुगतान नहीं किया गया है। इस अवधि के लिए निगम के 47 पार्षदों और महापौर का कुल 1.43 करोड़ का मानदेय बकाया है। उच्च न्यायालय के द्वारा जिन 22 याचिकाकर्ता पार्षदों और महापौर के लिए आदेश जारी किया है उन्हें आगामी 3 माह में 67 लाख का भुगतान करना होगा।

# शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने वाला आरोपी को मणिपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया

-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 12 दिसम्बर 2025 (घटती-घटना)।

दैहिक शोषण के उक्त मामले में पीड़िता ने थाना मणिपुर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 01.06.2024 से नगर ऊंटारी झारखंड का करुणा कुमार द्वारा शादी करने का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाया एवं बाद में शादी से इनकार कर दिया है। पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना मणिपुर में अपराध क्रमांक 328/2025 धारा 376(2)(एन),506 भा.दं.सं. के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान थाना मणिपुर पुलिस द्वारा नगर उँटरी झारखंड जाकर स्थानीय पुलिस एवं साइबर सेल अंबिकापुर के सहयोग से आरोपी के संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई। आरोपी करुणा कुमार पिता देव कुमार राम, उम्र 28 वर्ष, पता - तिवरियाम, थाना नगर ऊंटारी, जिला गढ़वा (झारखंड) को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया जिसने अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रकरण में अग्रीम कार्रवाई करते हुए दिनांक 12/12/2025 को आरोपी का मेडिकल परीक्षण कराया जाकर आरोपी को गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी उपनिरीक्षक सी. पी. तिवारी, सऊनि अनिल पांडे,आरक्षक उमाशंकर साहू, सत्येंद्र दुबे, अनिल सिंह, रामाशंकर यादव एवं साइबर सेल से आरक्षक रमेश राजवाड़े की सक्रिय भूमिका रही।

# जीवन ज्योति सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल का आईवीएफ सेंटर का उद्घाटन

-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 12 दिसम्बर 2025 (घटती-घटना)।

जीवन ज्योति सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल ने अपने 15 वर्षों के सफलतापूर्वक कार्यकाल के उपलक्ष्य में निसंतान दंपतियों के लिए आईवीएफ (टेस्ट ट्यूब बेबी) केंद्र का भव्य शुभारंभ किया। इस केंद्र के खुलने से अब अंबिकापुर और पूरे सरगुजा संभाग के दंपतियों को संतान सुख पाने के लिए मेट्रो सिटी जाने की आवश्यकता नहीं होगी। जीवन ज्योति हॉस्पिटल में सभी जांच, उपचार, सोनोग्राफी,ब्लड टेस्ट और आईवीएफ की प्रक्रिया एक ही स्थान पर पूरी की जाएगी, जिससे समय, पैसा और मानसिक तनाव की बचत होगी। साथ ही,महिलाओं के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल भी सुनिश्चित किया गया है। आईवीएफ सेंटर का शुभारंभ कृषि मंत्री राम विचार नेताम ने वर्चुअल रूप से किया। इस दौरान, उन्होंने जीवन ज्योति हॉस्पिटल और क्षेत्र के लोगों को इस नए स्वास्थ्य सुविधा के लिए बधाई दी। कार्यक्रम में जीवन ज्योति अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा एक प्रभावी नाटक का मंचन किया गया,जिसमें अंधविश्वास से ऊपर उठकर चिकित्सा सुविधाओं का लाभ लेने की प्रेरणा दी गई। डॉ. स्नेहा सिंह (आईवीएफ विशेषज्ञ) ने बताया कि इस आईवीएफ क्लिनिक के उद्घाटन से उन दंपतियों को बड़ी मदद मिलेगी जो संतान सुख की इच्छा रखते हैं। आईवीएफ तकनीक के माध्यम से जन्म लेने वाले बच्चे स्वस्थ होते हैं और पूरी तरह सामान्य जीवन जीते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ और सरगुजा क्षेत्र में बांझपन के मुख्य कारणों में तनाव, देर से शादी, हार्मोनल बदलाव और कमजोर शुक्राणु जैसी समस्याएं शामिल हैं। सही समय पर जांच और उपचार से अधिकांश दंपति प्राकृतिक रूप से माता-पिता बन सकते हैं। आईवीएफ की प्रक्रिया दो महीने में पूरी होती है और यह आसान, कम दर्द वाली और प्रभावी होती है। डॉ. आकाश सिंह, हॉस्पिटल के एमडी, ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आईवीएफ के लिए आवश्यक सभी जांच और उपचार सुविधाएं अब मेट्रो सिटीज जैसी उपलब्ध होंगी। अत्यधिक सटीक उपकरणों के साथ, यहां विश्वसनीय और प्रभावी उपचार प्रदान किया जाएगा। डॉ. स्नेहा सिंह ने आगे बताया कि सरगुजा क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने के लिए वे लोगों तक पहुंचेंगे,ताकि दंपति बिना किसी झिझक के आईवीएफ की प्रक्रिया को अपनाएं। अब सरगुजा वासियों को मेट्रो सिटीज की तुलना में यहां ही पूरी चिकित्सा सहायता प्राप्त होगी। जीवन ज्योति हॉस्पिटल की डायरेक्टर संध्या सिंह ने बताया कि इस आईवीएफ सेंटर का उद्देश्य यह है कि सामाजिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले दंपति भी संतान सुख से वंचित न रहें।

उन्होंने कहा कि यहां आईवीएफ केंद्र का लाभ साधारण लोग भी उठा सकते हैं,ताकि कोई भी संतान सुख से वंचित न रहे। इस उद्घाटन कार्यक्रम में डॉ. जेके सिंह, डॉ. एमपी अग्रवाल, बब्बन जी पांडे, विजय सोनी,त्रिलोक कपूर कुशवाहा, मनीष सिंह, गीता प्रजापति, वंदना दत्ता और कई अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति मौजूद थे।

## पुलिस अधिकारी कर्मचारियों में बेहतर अनुशासन,टर्न आउट एवं फिटनेस हेतु जनरल परेड का आयोजन

# वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा राजेश अग्रवाल ने ली जनरल परेड की सलामी

## एवं अधिकारी कर्मचारियों के अनुशासन,फिटनेस एवं टर्न आउट की समीक्षा की

-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 12 दिसम्बर 2025 (घटती-घटना)।

पुलिस लाइन अंबिकापुर में जनरल परेड का आयोजन किया गया जिसमें परेड कमांडर श्रीमती तृप्ति सिंह राजपूत रक्षित निरीक्षक, रक्षित केंद्र अम्बिकापुर के द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा श्री राजेश अग्रवाल (भा.पु.से.) को परेड की सलामी दी गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा के द्वारा पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के अनुशासन, फ़िटनेस एवं टर्न आउट का निरीक्षण किया गया जिसमे पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज श्री दीपक कुमार झा (भा.पु.से.) के निर्देशन में अनफिट पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के फिटनेस हेतु केपी गाँव सीआरपीएफ कैम्प में चलाए जा रहे एक माह के प्रशिक्षण कार्यक्रम के पश्चात परेड में सम्मिलित होने पर उनके निरीक्षण दौरान ज्ञात हुआ कि प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारी कर्मचारियों के वजन में पाँच किलो तक कमी आई है, स्वास्थ्य सुधार हुआ है एवं उक्त प्रक्षिक्षण की प्रक्रिया अभी जारी रहेगी। परेड में सम्मिलित अधिकारी कर्मचारियों को बेहतर अनुशासन एवं टर्न आउट हेतु उनके उत्साहवर्धन हेतु उचित इनाम भी दिये एवं अधिकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण में बढ़ चढ़कर भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया। पुलिस अधिकारी कर्मचारियों ने सहायक उपनिरीक्षक चैन साय के कुशल बैंड टीम की धुन पर परेड किया जो परेड में उपस्थित राजपत्रित अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक है श्री अमोलक सिंह ढिल्लो, उप पुलिस अधीक्षक श्री तुल सिंह पट्टावी, उप पुलिस अधीक्षक श्री सुरेश भगत द्वारा अधिकारी कर्मचारियों की ड्रिल अभ्यास चेक किया।

# अंबिकापुर दिल्ली ट्रेन को सप्ताह में 2 दिन करने सांसद चिंतामणि महराज ने लोकसभा में रखी मांग

-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 12 दिसम्बर 2025 (घटती-घटना)।

सरगुजा सांसद श्री चिंतामणि महराज ने आज लोकसभा में अंबिकापुर-नई दिल्ली एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 22407) की आवृत्ति सप्ताह में एक दिन से बढ़ाकर दो दिन किए जाने की महत्वपूर्ण माँग रखी। सरगुजा सांसद के इस प्रयास से अंबिकापुर से दिल्ली जाने वाले रेट रेल यात्रियों को काफी प्रसन्नता हुई है। आज संसद की इस पहल पर खुशी जाहिर करके सरगुजा के कई यात्रियों ने अंबिकापुर दिल्ली यात्रा को और बेहतर बनाने के लिए सांसद सरगुजा को कुछ जरूरी सुझाव भेजे हैं,और अंबिकापुर रायपुर इंटरसिटी और नागपुर तक कनेक्टिविटी बढ़ाने की मांग भी रखी है। सांसद सरगुजा ने सदन को अवगत कराया कि यह ट्रेन वर्तमान में सप्ताह में केवल एक दिन चलती है, जिसके कारण सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर और कोरिया जिलों के हजारों छात्रों, मरीजों, नौकरीपेशा लोगों और व्यापारियों को दिल्ली यात्रा के दौरान टिकट न मिलना, लंबी प्रतीक्षा सूची और भीड़ जैसी गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्षेत्र की आवश्यकताओं और जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए, श्री चिंतामणि महराज ने अनुरोध किया है कि ट्रेन की आवृत्ति बढ़ाने पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लिया जाए, ताकि आमजन को राहत मिल सके और दिल्ली आवागमन सुगम हो।

# अंबिकापुर में ठंड से मौत के बाद एसएसपी की खास पहल,अब पुलिस की नाइट पेट्रोलिंग टीम कांपते लोगों को बांटेगी कंबल

-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 12 दिसम्बर 2025 (घटती-घटना)।

शहर के बस स्टैंड में मंगलवार की रात एक व्यक्ति की ठंड से मौत हो गई थी, उसका शव बुधवार को मिला था। उसका शरीर अकड़ा हुआ था। ठंड से होने वाली मौत को देखते हुए सरगुजा एसएसपी राजेश अग्रवाल ने एक मानवीय पहल की है। उन्होंने पुलिस की नाइट पेट्रोलिंग टीमों को अपने साथ 10-10 कंबल रखने के निर्देश दिए हैं,ताकि कडक़ड़ाती ठंड में इधर-उधर घूम लोगों को वितरित किया जा सके। एसएसपी की इस पहल की पुलिस महकमे सहित शहर में चर्चा हो रही है। अंबिकापुर समेत सरगुजा संभाग में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पारा 5 डिग्री व उससे नीचे जा रहा है। इस कडक़ड़ाती ठंड में कई ऐसे लोग भी शहर व आस-पास के इलाके में घूमते देखे जाते हैं जिनके पास पर्याप्त कपड़े नहीं होते। वे सारी रात ठंड में ही गुजारते हैं। ऐसे लोगों को ठंड से बचाने सरगुजा एसएसपी राजेश अग्रवाल ने एक खास पहल की है। उन्होंने रात्रि में गश्त करने वाली पुलिस पेट्रोलिंग टीम को अपने साथ वाहन में 10-10 कंबल रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि यदि ऐसे लोग घूमते दिखें तो उन्हें वे कंबल देकर ठंड से राहत दिलाएं।

# प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय सरगुजा के अंतर्गत सभी न्यायालयों में हाईब्रिड नेशनल लोक अदालत का आयोजन

-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 12 दिसम्बर 2025 (घटती-घटना)।

राष्ट्र विधिक सेवा प्राधिकरण,नई दिल्ली तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार मान. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरगुजा (अम्बिकापुर ) (छ.ग.) श्री के. एल. चरयाणी जी के मार्गदर्शन में आगामी दिनांक 13/12/2025 दिन - शनिवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय सरगुजा (अम्बिकापुर ) (छ.ग.) के अंतर्गत सभी न्यायालयों में, जिसमें व्यवहार न्यायालय सीतापुर भी सम्मिलित है,में हाईब्रिड नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उक्त हाईब्रिड नेशनल लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों की आपसी सहमति के आधार पर मामलों का राजीनामा के माध्यम से निराकरण करने हेतु खण्डपीठ का गठन किया जा चुका है। उक्त खण्डपीठों में निम्न प्रकार के प्रकरणों का आपसी सहमति के आधार पर राजीनामा द्वारा निपटारा किया जा सकता है...राजीनामा योग्य दाण्डिक प्रकरण,व्यवहार प्रकरण चैक बाउंस प्रकरण,पारिवारिक विवाद,दुह टिना संबंधी दावा, मजदूरों सें संबंधित प्रकरण, भूमि अधिग्रहण प्रकरण, राजस्व प्रकरण, विद्युत चोरी संबंधी प्रकरण जैसे प्री-लिटीगेशन के प्रकरणों का भी निराकरण आपसी सहमति के माध्यम से किया जा सकता है। पक्षकारगण अपने मामले का निराकरण आपसी सहमति से करने हेतु संबंधित खण्डपीठ के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के अलावा वर्चुअल विडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से भी उपस्थित हो सकते हैं।

# शुभम जायसवाल को अम्बिकापुर विधानसभा के लिए बनाया गया युवा कांग्रेस का अध्यक्ष

-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 12 दिसम्बर 2025 (घटती-घटना)।

युवा कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष आकाश शर्मा ने शुभम जायसवाल को अम्बिकापुर विधानसभा के लिए युवा कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस नियुक्ति से युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हर्ष व्याप्त है। अम्बिकापुर शहर ब्लॉक अध्यक्ष से प्रमोशन मिलने के साथ उनकी नियुक्ति युवा कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर हुई है। शुभम जायसवाल वर्तमान में नगर निगम अम्बिकापुर में पार्षद हैं। पूर्व में वे एनएसयूआई के सरगुजा जिले के उपाध्यक्ष पद पर कार्य कर चुके हैं।

## शोक सूचना

कोरिया के ग्राम पंचायत पटना निवासी मोहम्मद इसाक खान (उम्र 48 वर्ष) पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे, अल्लाह की मर्ज़ी से उनका जुमे के दिन इंतेक़ाल हो गया, उनके इंतक़ाल से पूरे खानदान और इलाक़े में गहरा सदमा है दो मासूम बच्चों के सर से बाप का साया उठ गया,मोहम्मद इसाक खान डीएव्ही पब्लिक स्कूल पांडवपार में बच्चों को लाने-ले जाने का काम करते थे और अपने हंसमुख व मिलनसार स्वभाव के लिए सबके चहेते थे,जनाज़े की नमाज़ शनिवार को सुबह 11 बजे पटना क़ब्रिस्तान में अदा की जाएगी,जिसके बाद तदफ़ीन की जाएगी, अल्लाह तआला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए,उनकी क़ब्र को रौशन करे और जन्नतुल फिरदौस में मुक़ाम अता फरमाए। **आमीन।**

**इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।**

# 'अमर लिपिक' को प्रमोशन,लेकिन कुर्सी वही...

## जिला प्रशासन की नीति पर फिर सवाल,क्या खनिज शाखा में सेटिंग कल्चर अमर है? या जिला खनिज शाखा में अटूट कब्जा!

## प्रमोशन मिला,पोस्टिंग नहीं बदली...क्या किसी अदृश्य शक्ति का संरक्षण? या प्रमोशन मिला,व्यवस्था नहीं बदली...

- खनिज शाखा में वर्षों से जमे कर्मचारी को फिर से 'यथावत'आदेश, अधिकारियों की चुप्पी क्यों?
- पहले उठा था सवाल एक ही कुर्सी पर वर्षों से जमे अमर लिपिक...
- एक्सक्लूसिव 7 जिला खनिज न्यास का अमर लिपिक अब प्रमोट भी...लेकिन सीट वही क्यों?
- पदोन्नति आदेश ने और बढ़ा दिए सवाल–क्या 'यथावत पोस्टिंग'से किसी खास को संरक्षण?

-रवि सिंह-

कोरिया,12 दिसम्बर 2025 (घटती-घटना)।

कुछ सप्ताह पूर्व प्रकाशित समाचार जिला खनिज न्यास का अमर लिपिक ने जिला प्रशासन और खनिज शाखा में हलचल मचा दी थी,रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया था कि जिला खनिज न्यास का एक लिपिक,वर्षों से एक ही सीट पर जमे बैठा था, भर्ती, संपत्ति, पूर्व चयन, और कथित प्रभावशीलता पर सवाल उठ रहे थे,और अधिकारियों में उसे हटाने की 'हिम्मत'न होने की चर्चाएँ जोरों पर थीं,रिपोर्ट में यह भी उल्लेख था कि खनिज जैसी संवेदनशील शाखा में बार-बार वही स्टाफ रखना जोखिमपूर्ण और संदिग्ध माना जाता है, रिपोर्टिंग का उद्देश्य किसी व्यक्ति को निशाना बनाना नहीं प्रणाली की कमजोरियों को उजागर करना है, और इस समय सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि खनिज शाखा में 'अमर लिपिक' की स्थिति अब प्रमोशन के साथ और मजबूत होती दिखाई दे रही है।

### अमर लिपिक की अमर कुर्सी क्या जिला खनिज शाखा एक व्यक्ति-आधारित व्यवस्था बन चुकी है?

जिला खनिज न्यास शाखा से जुड़ा विवाद कोई नया नहीं है। महीनों से यह चर्चा गर्म थी कि एक ही लिपिक वर्षों से लगातार उसी सीट पर बैठा है भर्ती से लेकर फाइल मूवमेंट, संपत्ति, रखरखाव, खनिज परिवहन, सभी प्रक्रियाओं की 'चाभी' एक ही व्यक्ति के हाथों में केंद्रित है, प्रश्न उठाए गए थे कि क्या यह विभाग किसी व्यक्ति के इर्द-गिर्द चलता है, या किसी ऐसी अदृश्य संरचना के अधीन है जिसे छूने की हिम्मत जिला प्रशासन में किसी अधिकारी के पास नहीं? पहले प्रकाशित रिपोर्ट जिला खनिज न्यास का अमर लिपिक ने इस मामले को जिला स्तरीय बहस का मुद्दा बना दिया था। फाइलें जमीं थीं, व्यवस्थाएं कठोर थीं और एक ही सीट पर वर्षों तक जमे रहने का यह रिकॉर्ड कई विभागों में शायद ही देखने को मिलता हो, और अब, हाल ही में जारी पदोन्नति आदेश ने इस विवाद में एक नया अध्याय जोड़ दिया है लिपिक को प्रमोट तो किया गया, लेकिन पोस्टिंग वही रखी गई, नई सीट नहीं, नया विभाग नहीं, नया दायित्व नहीं सबकुछ जस का तस।

### अब नया मोड़: पदोन्नति आदेश में भी यथावत पदस्थापना-

जारी हुए ताजा आदेश में जिला खनिज शाखा के जिस लिपिक पर सवाल उठे थे, उन्हीं सहित कई कर्मचारियों को सहायक ग्रेड-3 से सहायक ग्रेड-2 में प्रमोशन दे दिया गया, लेकिन पोस्टिंग वहीं की वहीं! न शाखा बदली...न विभाग बदला...न पदस्थापना बदली...बस प्रमोशन मिला और सीट वही रखी गई, यानी पहले से उठ रहे सवालों के बीच भी प्रशासन ने यथावत पोस्टिंग का रास्ता चुन लिया।

### बड़ा सवाल: क्या यह सिस्टम किसी का संरक्षण कर रहा है?-

जब पहले से ही खनिज शाखा में एक ही सीट पर वर्षों तक बैठे रहने पर सवाल उठ रहे थे, तो स्थानांतरण नीति का पालन क्यों नहीं हुआ? संवेदनशील शाखाओं में लंबे समय तक एक ही कर्मचारी रखने पर प्रतिबंध क्यों नहीं लागू? यदि खनिज कार्यालय में पहले भी शिकायतें, चर्चाएँ और संपत्ति संबंधी सवाल रहे हैं, तो पदोन्नति के बाद भी उसी स्थान पर बनाए रखना किसका निर्णय?

### क्या प्रमोशन=स्थायी सेटिंग?

कर्मचारी संगठनों में चर्चा गर्म है जब प्रमोशन के बाद भी सीट न बदले, चेयर न बदले, काम न बदले...तो यह प्रमोशन है या पुरानी व्यवस्था का विस्तार? लोग पूछने लगे हैं जिले की ट्रांसफर नीति किसके लिए लागू होती है और किसके लिए नहीं? '

### पूर्व रिपोर्ट से जुड़ा एक और कनेक्शन...पहले की रिपोर्ट में तीन मुख्य मुद्दे उठे थे...

संपत्ति और अनुचित प्रभाव, कुर्सी पर वर्षों की पकड़, अधिकारियों की मजबूरी या मौन स्वीकृति? अब प्रमोशन आदेश में भी उसी स्टाफ को बिना बदले खनिज शाखा में ही रखा गया है, जिससे यह सवाल और गहरा हो गया है कि क्या खनिज शाखा में पूरी संरचना एक खास स्टाफ के इर्द-गिर्द चल रही है?

### चर्चाएँ: जिस कुर्सी पर सवाल थे,उस कुर्सी पर ही प्रमोशन के बाद भी टिके रहना क्या यह सामान्य है?

कार्यालयीन हलकों में चर्चा है कि यदि किसी शाखा में शिकायतें और अनियमितताओं पर पहले से ही चर्चा हो, और उसी शाखा में बैठे व्यक्ति को बिना बदले प्रमोशन दे दिया जाए, तो यह संदेश क्या देता है?

### संभावित असर: क्या जांच की जरूरत और मजबूत हो गई?

पहले की रिपोर्ट में यह भी उल्लेख था कि खनिज शाखा में करोड़ों की संपत्ति, संवेदनशील फाइलें, और पुरानी चयन प्रक्रिया संदेह के घेरे में रही हैं, अब प्रमोशन के बाद भी पोस्टिंग वही बनाए रखने से जनता में संदेह और गहरा हो गया है।

### जनता का सवाल: क्या यह प्रशासनिक मजबूरी या कुछ और...?

डेस्क से यह सवाल उठ रहा है क्या खनिज कार्यालय में ऐसा क्या है कि वर्षों से वही स्टाफ, वही कुर्सी, वही सेटिंग चलती रहती है? पूर्व प्रकाशित अमर लिपिक रिपोर्ट के बाद जो सुधार की उम्मीद थी...जो पारदर्शिता की अपेक्षा थी...वह पदोन्नति आदेश आते ही फिर से सवालों में घिर गई, क्योंकि प्रमोशन हुआ, लेकिन व्यवस्था वही और सवाल पहले से अब और बड़े हो गए।

### प्रमोशन के बाद भी कुर्सी वही क्यों?

यह सवाल सिर्फ प्रशासनिक निर्णय पर नहीं,बल्कि विभागीय पारदर्शिता पर भी उठता है, नियमों के अनुसार संवेदनशील शाखाओं में लंबे समय तक एक ही कर्मचारी की पोस्टिंग को टाला जाना चाहिए,खनिज शाखा खुद एक अत्यंत संवेदनशील शाखा मानी जाती है, जहाँ राजस्व, रॉयल्टी, खनिज परिवहन, निरीक्षण, और बड़ी मात्रा में फाइलें किसी भी जिले की आर्थिक दिशा तय करती हैं, ऐसे में, वर्षों से एक ही व्यक्ति का एक ही सीट पर बने रहना अपने आप में प्रश्नचिह्न है।

### क्या यह सिर्फ संयोग है? या सोची-समझी संरचना?

ताजा प्रमोशन आदेश इसलिए और संदेह बढ़ाता है क्योंकि जब पूरे जिले में पदोन्नति के साथ पोस्टिंग बदली जाती है, जब संवेदनशील शाखाओं में अक्सर रोटेशन किया जाता है, जब एक ही सीट पर वर्षों तक जमे रहना शासन की नीति के विरुद्ध है, तब खनिज शाखा में इतना विशेष संरक्षण क्यों दिखाई देता है? प्रमोशन मिलना एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है, लेकिन प्रमोशन के बाद भी उसी कुर्सी पर बने रहना अब बहस का विषय बन चुका है।

### अधिकारियों की चुप्पी, सबसे बड़ा संकेत...

जब किसी मामले पर लगातार चर्चाएँ उठें, जब मीडिया रिपोर्ट आएँ, जब कर्मचारी संगठन भी सवाल उठाएँ...फिर भी न तबादला, न रोटेशन, न विभागीय समीक्षा, और अब प्रमोशन के बाद भी यथावत तो यह चुप्पी कहीं न कहीं गहरे संकेतों की ओर इशारा करती है, क्या जिला प्रशासन भी अब यह स्वीकार कर चुका है कि यह अमर कुर्सी कभी खाली नहीं होगी? ये सवाल जनता पूछ रही है और प्रशासन इससे कब तक बचता रहेगा?

### व्यवस्था वही, कुर्सी वही,और अब प्रमोशन भी वही... क्या यही है नई प्रशासनिक नीति?

क्या आदेश का निष्कर्ष यही है यह सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं, यह पूरे जिले की प्रशासनिक विश्वसनीयता पर प्रश्न है, अगर संवेदनशील विभागों में जवाबदेही नहीं बनेगी, अगर वर्षों तक एक ही कुर्सी पर कब्जा बना रहेगा, अगर प्रमोशन के बाद भी पोस्टिंग न बदले, तो फिर जनता सवाल पूछेगी और पूछना उसका अधिकार है।

- सवाल ये नहीं कि प्रमोशन क्यों दिया गया...सवाल यह है कि सीट क्यों नहीं बदली गई?
- सवाल: क्या खनिज शाखा में किसी 'स्थायी व्यवस्था'को बचाया जा रहा है?
- सवाल: क्या संवेदनशील फाइलों पर पकड़ कमजोर नहीं पड़ने दी जा रही?
- सवाल: क्या रोटेशन नीति सिर्फ कागजों तक सीमित है?
- सवाल: क्या किसी की 'सुविधा 'इस व्यवस्था पर भारी है?

### क्या खनिज शाखा में कोई प्रभावी नेटवर्क सक्रिय है?-

पिछली रिपोर्ट के बाद से लगातार यह चर्चा चल रही है कि खनिज शाखा में फाइलों का प्रवाह,अनुमोदन और दस्तावेजी कार्यवाही कुछ चुनिंदा लोगों में सीमित रहती है, यह भी सुनने में आया कि संपत्ति और रहन-सहन पर उठे सवालों को कभी जांच का विषय नहीं बनाया गया, अब प्रमोशन आदेश ने इन चर्चाओं को और हवा दे दी है।

## कलेक्टर ने कुनकुरी नेत्रहीन आवासीय विद्यालय का किया निरीक्षण, बच्चों की मांगों पर दिए तत्काल निर्देश

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,12 दिसम्बर 2025 (घटती-घटना)।

कलेक्टर विलास भोसकर आज बतौली ब्लॉक के कुनकुरी स्थित नेत्रहीन आवासीय विद्यालय पहुंचे। उन्होंने विद्यालय में शिक्षा, आवास, भोजन एवं बच्चों की देखभाल से संबंधित व्यवस्थाओं का अवलोकन कर संचालित सुविधाओं की जानकारी ली। कलेक्टर ने बच्चों से संवाद कर उनकी आवश्यकताओं और दैनिक गतिविधियों के बारे में भी पूछा। निरीक्षण के दौरान बच्चों ने कलेक्टर से फुटबॉल और क्रिकेट बैट की मांग रखी। कलेक्टर श्री भोसकर ने उनकी मांगों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक सामग्रियां तुरंत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दिव्यांग बच्चों की जरूरतें प्राथमिकता के आधार पर पूरी की जाएं, ताकि उन्हें सीखने, खेलने और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए

बेहतर वातावरण मिल सके। इसी दौरान बच्चों ने शैक्षणिक भ्रमण की इच्छा भी व्यक्त की, जिस पर कलेक्टर ने बच्चों को उदयपुर के रामगढ़ भ्रमण के लिए ले जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे भ्रमण बच्चों के अनुभवों का विस्तार करते हैं और उनके सामाजिक एवं मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस दौरान एसडीएम श्री रामसिंह ठाकुर, तहसीलदार एवं अन्य विभागीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

## पुलिस आरक्षक भर्ती परिणामों से संबंधित शिकायतों और समस्याओं के निराकरण हेतु डीआईजी/एसएसपी सूरजपुर ने गठित किया हेल्प डेस्क समिति

-संवाददाता-

सूरजपुर,12 दिसम्बर 2025 (घटती-घटना)।

पुलिस आरक्षक भर्ती वर्ष 2023-24 अन्तर्गत जारी भर्ती परिणामों से संबंधित शिकायतों और समस्याओं के निराकरण हेतु इकाई स्तर पर डीआईजी व एसएसपी सूरजपुर श्री प्रशांत कुमार ठाकुर की अध्यक्षता में दर्शित अनुसार हेल्प डेस्क समिति गठित की गई है जिसमें नोडल अधिकारी डीएसपी मुख्यालय महालक्ष्मी कुलदीप को बनाया गया साथ ही इनके सहायतार्थ उनि(अ) महेश पैंकरा मुख्य लिपिक व उनि(अ) अखिलेश सिंह स्थापना प्रभारी रहेंगे। हेल्प डेस्क 2 शिफ्ट में होगा संचालित। हेल्प डेस्क का प्रथम शिफ्ट प्रातः 10.30 से दोपहर 12.30 बजे तक का रहेगा जिसमें प्रधान आरक्षक 64 नृपेन्द्र सिंह व आरक्षक 600 नितिन साहू जिला विशेष शाखा तैनात रहेंगे। वहीं द्वितीय शिफ्ट दोपहर 3 बजे से सायं 5.30 बजे तक रहेगा जिसमें प्रधान आरक्षक 221 हरिशंकर यादव व आरक्षक 894 अनीश तिवारी जिला विशेष शाखा तैनात रहेंगे।

उपरोक्त हेल्प डेस्क जिला पुलिस कार्यालय में दोनों शिफ्टों में तत्संबंधी शिकायतें प्राप्त कर नोडल अधिकारी के माध्यम से भर्ती समिति से जानकारी प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरकर्ता से अनुमोदन उपरान्त तदनुसार आवेदक/शिकायतकर्ताओं को जानकारी उपलब्ध कराएगी।

### व्यापार समाचार

## लगातार दूसरे दिन मजबूती के साथ बंद हुआ शेयर बाजार निवेशकों ने एक दिन में कमाए 3.61 लाख करोड़ हुई

**नई दिल्ली,12 दिसम्बर 2025।** घरेलू शेयर बाजार शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन मजबूती के साथ बंद हुआ। शुक्रवार को कारोबार की शुरुआत बढ़त के साथ हुई थी। बाजार खुलने के बाद खरीदारी के सपोर्ट से सेंसेक्स और निफ्टी की चाल में और तेजी आ गई। हालांकि थोड़ी देर बाद ही मुनाफा वसूली शुरू हो जाने के कारण इस सूचकांक की चाल में गिरावट का रुख भी बन गया। दोपहर 11 बजे के बाद खरीदारों ने एक बार फिर लिवाली का जोर बनाया, जिससे शेयर बाजार की चाल में दोबारा तेजी आ गई। पूरे दिन के कारोबार के बाद सेंसेक्स 0.57 प्रतिशत और निफ्टी 0.53 प्रतिशत की तेजी के साथ बंद हुए। शुक्रवार को कारोबार के दौरान मेटल सेक्टर के शेयरों में सबसे अधिक खरीदारी होती रही, जिसकी वजह से निफ्टी के मेटल इंडेक्स ने 2.63 प्रतिशत की छलांग लगाई। इसके अलावा निफ्टी का रियल्टी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑयल एंड गैस और बैंकिंग इंडेक्स में भी 1 प्रतिशत तक की तेजी दर्ज की गई। ब्रॉडर मार्केट में भी शुक्रवार को लगातार खरीदारी होती रही, जिसके कारण बीएसई का मिडकैप इंडेक्स 1.14 प्रतिशत की

मजबूती के साथ बंद हुआ। इसी तरह स्मॉलकैप इंडेक्स ने 0.65 प्रतिशत की तेजी के साथ शुक्रवार को कारोबार का अंत किया। शुक्रवार को शेयर बाजार में आई मजबूती के कारण स्टॉक मार्केट के निवेशकों की संपत्ति में साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक की बढ़ोतरी हो गई। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन शुक्रवार को कारोबार के बाद बढ़ कर 470.25 लाख करोड़ रुपये (अनंतिम) हो गया। जबकि पिछले कारोबारी दिन यानी गुरुवार को इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 466.64 लाख करोड़ रुपये था। इस तरह निवेशकों को शुक्रवार को कारोबार से करीब 3.61 लाख करोड़ रुपये का मुनाफा हो गया। शुक्रवार को दिन भर के कारोबार में बीएसई में 4,356 शेयरों में एक्टिव ट्रेडिंग हुई। इसी तरह सेंसेक्स में शामिल 30 शेयरों में से 23 शेयर बढ़त के साथ और 7 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। जबकि निफ्टी में शामिल 50 शेयरों में से 35 शेयर हरे निशान में और 15 शेयर लाल निशान में बंद हुए। बीएसई का सेंसेक्स शुक्रवार को 232.90 अंक की मजबूती के साथ 85,051.03 अंक के स्तर पर खुला। कारोबार की शुरुआत होते ही खरीदारी के सपोर्ट से ये सूचकांक उछल कर 85,282.76 अंक के स्तर तक पहुंच गया। हालांकि पहले 10 मिनट के कारोबार के बाद ही मुनाफा वसूली शुरू हो जाने के कारण सेंसेक्स फिसल कर 84,956.74 अंक के स्तर तक गिर गया। दोपहर 11 बजे के बाद एक बार फिर खरीदारों ने लिवाली का जोर बना दिया, जिससे इस सूचकांक की चाल में दोबारा तेजी आ गई। बाजार में दिन भर की खरीद बिक्री के बाद सेंसेक्स 449.53 अंक की बढ़त के साथ 85,267.66 अंक के स्तर पर बंद हुआ।

## पहली बार चांदी 2 लाख रुपये प्रति किलो के ऊपर पहुंची,सोना भी उछला

**नई दिल्ली,12 दिसम्बर 2025।** पहली बार चांदी 2 लाख रुपये प्रति किलो के पार पहुंच गई है। फेडरल रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में कटौती और मांग बढ़ने के बाद मल्टी कमोडिटी मार्केट (एमसीएक्सा) पर चांदी में ये उछाल आया है। चांदी 1600 रुपये उछलकर 2,00,510 रुपये प्रति किलो पर कारोबार कर रही है। वहीं सोने में भी रिकॉर्ड तेजी रही। एमसीएक्स पर सोना शुक्रवार को करीब 2500 रुपये चढ़कर 1,34,966 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, ये इसका रिकॉर्ड ऊंचा स्तर है। एमसीएक्स पर सोने के वायदा भाव लगभग 1,32,700 रुपए और चांदी के भाव 1,97,850 रुपए के आसपास

कारोबार कर रहे थे। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने के फरवरी कॉन्ट्रेक्ट की शुरुआत मामूली गिरावट के साथ 1,32,442 रुपए पर हुई, जबकि पिछला बंद भाव 1,32,469 रुपए था। शुरुआती कमजोरी के बाद सोने में खरीदारी बढ़ी और यह कॉन्ट्रेक्ट 1,32,673 रुपए पर पहुंच गया, जो लगभग 204 रुपए की तेजी दर्शाता है। दिन के दौरान सोना 1,32,764 रुपए के रिकॉर्ड उच्च स्तर तक पहुंचा, जबकि 1,32,400 रुपए इसका दिन का निचला स्तर रहा।

# प्रशासन को कहां से मिलते हैं ऐसे किसान, जो नहीं हैं परेशान ?

**इक्का-दुक्का वीडियो से पीठ थपथपाने की कोशिश,मगर धरातल पर तस्वीर बिल्कुल उलट ...**

**खरीदी सीमा 2000 से घटाकर 700 क्विंटल, सरकारी फैसले ने अव्यवस्था को न्योता दिया ...**

**किसान बोला मोबाइल घिस गया टोकन के इंतजार में, फिर भी हाथ खाली ...**

**समिति के तौल यंत्रों में छेड़छाड़ ? हर किसान के बोरे में समान कमी से बड़ा खेल उजागर ...**

**आधिकारिक कटौती तय फिर आधा किलो धान क्यों ? नियमों को ताक पर रखकर चल रही है उगाही**

**अध्यक्ष-प्रबंधक-कर्मचारी का त्रिकोणीय गठजोड़...पूरी प्रक्रिया पर हावी 'वसूली तंत्र' ...**

**सरकारी चमक-दमक वाले वीडियो बनाम किसान की जमीनी हकीकत...कौन सच बोले ?**

**किसानों में डर ...सीमित खरीदी ऐसे ही रही ...तो शायद हम धान बेच ही न पाएं ...**

-राजन पाण्डेय-

**कोरिया,12 दिसंबर 2025 (घटती-घटना)।**

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर सरकार और प्रशासन लगातार यह दावा कर रहे हैं कि प्रदेश में खरीदी प्रक्रिया निर्विघ्न,सुचारु और किसानों के हितों के अनुरूप चल रही है,दावा है हर किसान संतुष्ट है,हर बोरी धान की खरीदी सहज है,इन दावों के समर्थन में जनसंपर्क विभाग और जिला प्रशासन रोज़ किसी न किसी इक्का-दुक्का किसान का वीडियो जारी कर यह संदेश देने में जुटा है कि सब कुछ सामान्य है,लेकिन सोशल मीडिया पर चल रही सैकड़ों समस्याग्रस्त वीडियो और किसानों की पीड़ा बयान करता मेहनतकश चेहरा बताता है सच्चाई बिल्कुल कुछ और है।

धान खरीदी प्रारंभ होने के लगभग एक माह हो चुके हैं। खरीदी पूर्व किसानों के सुविधा के लिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन द्वारा अनेक दावे किए गए थे। इन दावों के समर्थन में राज्य सरकार, जिला प्रशासन के साथ-साथ जनसंपर्क विभाग की टीम के द्वारा समाचार-पत्र, पोस्ट,विज्ञापन और सोशल मीडिया के उपयोग की सहायता से कुछ एक स्थान के इक्का दुक्का वीडियो और खबर डालकर जनता के बीच यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है,कि वर्तमान में इस सरकार में किसानों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। और किसान सुगमता पूर्वक, निर्बाध रूप से अपनी उपार्जित फसल समितियों में विक्रय कर रहे हैं,ऑनलाइन टोकन की व्यवस्था हो या 24 घंटे के भीतर भुगतान की बात,सरकार के दावे भले ही कुछ भी हों, परंतु हकीकत एन उलट है,अधिकांश किसान ऑनलाइन टोकन व्यवस्था ऐप से बुरी तरह परेशान हैं। उनका कहना है कि एक तो यह ऐप चलता नहीं और गलती से खुल जाए तब तक खरीदी की सीमा पूर्ण हो चुकी होती है। किसान कैसे दिनों से केवल टोकन कटने के लिए कतार में हैं, और इंतजार कर रहे हैं। ऑनलाइन टोकन के अतिरिक्त समितियों में धान विक्रय के लिए टोकन काटने की व्यवस्था दी गई है, परंतु अधिकांश किसानों का आरोप है कि समिति सदस्य,कर्मचारी टोकन काटने की एवज में किसानों से अवैध वसूली करने में लिप्त हैं। जिनमें कई समितियों के वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हैं।

## प्रति दिवस सीमित खरीदी किसानों की समस्या का बड़ा कारण

किसानों से उपार्जित फसल का एक-एक दाना समर्थन मूल्य में खरीदने का दावा करने वाली वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस बार प्रतिदिन समितियों में धान खरीदने की सीमा को सीमित एवं प्रतिबंधित कर दिया है। जहां पहले के वर्षों में समितियों में प्रति दिवस लगभग 2000 क्विंटल की खरीदी होती थी,वहीं इस वर्ष समितियों में केवल लगभग साढे 700 क्विंटल प्रति दिवस की खरीदी निर्धारित की गई है। जिसके लिए टोकन कटना भी एक-एक दिन के हिसाब से तय किया गया है, और यही कारण है कि प्रदेश के अधिकांश किसान इस व्यवस्था के कारण भारी संकट और समस्या में हैं, क्योंकि सीमित खरीदी होने की वजह से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यमों से टोकन कट नहीं रहे। और किसान कभी मोबाइल, कभी चॉइस सेंटर, तो कभी समितियों के चक्कर काटते हुए आमतौर पर देखे जा रहे हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, कि यदि खरीदी की सीमा को समय रहते नहीं बढ़ाया गया तो किसानों के मन में इस बात का भी भय व्याप्त है की वह अपना धान बेच भी पाएंगे या नहीं। और किसानों की इन्हीं मजबूरी का लाभ समितियों में पदस्थ कर्मचारी और अध्यक्ष उठा रहे हैं, और टोकन काटने के एवज में अवैध वसूली की बात सामने आ रही है।

## सीमित खरीदी ने बिगाड़ा पूरा सिस्टम

इस बार सरकार ने समितियों में प्रतिदिन खरीदी की सीमा को अचानक घटाकर लगभग 2000 क्विंटल से सीधे 700-750 क्विंटल कर दिया, यही निर्णय धान खरीदी की पूरी प्रक्रिया की जड़ में बैठा सबसे बड़ा संकट है, सीमित खरीदी ? सीमित टोकन, सीमित टोकन? लंबी कतारें किसानों की बेचैनी और इसी अव्यवस्था का लाभ उठाते कुछ कर्मचारी और समिति पदाधिकारी कर रहे हैं अवैध वसूली किसानों का कहना है कि हम धान बेचेंगे भी या नहीं, यह भी अब किस्मत पर निर्भर हो गया है।

## क्या तौल कांटे 'माइनस' में सेट हैं ?

किसानों का गंभीर आरोप वे घर से जो तौलाई कर धान ला रहे हैं, समिति के तौल कांटे में उसका वजन निश्चित मात्रा में कम मिल रहा है, अलग-अलग किसानों में वजन का अंतर बिल्कुल समान, अलग-अलग तौल यंत्रों में भी अंतर और शिकायतों की संख्या सैकड़ों में यह संकेत है कि तौल मशीनों में छेड़छाड़ कर अवैध उगाही की जा रही है, यह सिर्फ तकनीकी त्रुटि नहीं, बल्कि भारी वित्तीय अनियमितता का संकेत है।

## अध्यक्ष और समिति सदस्यः जिनसे उम्मीद,वे ही निकले बेवफ़ा

किसानों के प्रतिनिधि के रूप में बैठे मनोनीत समिति अध्यक्ष,जो किसानों की आवाज़ उठाने की जिम्मेदारी रखते हैं, इस बार किसानों के साथ नहीं समिति कर्मचारियों के साथ खड़े दिख रहे हैं, सूत्रों के अनुसार कई अध्यक्ष पहले ही समिति प्रबंधकों से अपना हिस्सा सेट कर चुके हैं इसकी भरपाई किसानों से करवाने के लिए तौल,टोकन और खरीदी प्रक्रिया में दबाव,किसानों की शिकायत को दबाने के प्रयास,यह स्थिति बताती है कि समिति,प्रबंधन और अध्यक्ष–एक त्रिकोणीय गठजोड़ बनाकर किसानों को आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे हैं।

## प्रशासन को चाहिए जांच न कि दावा...

यदि धान खरीदी व्यवस्था इतनी ही पारदर्शी होती, तो- किसानों की इतनी बड़ी संख्या शिकायत क्यों कर रही?, सोशल मीडिया समस्याओं से अटा पड़ा क्यों है? तौल मशीनों में समान अंतर क्यों पाया जा रहा? टोकन के लिए अवैध वसूली क्यों हो रही है? प्रशासन को चाहिए कि तौल यंत्रों का पुनः परीक्षण करवाए, टोकन व्यवस्था की जांच करे, सीमित खरीदी के निर्णय पर पुनर्विचार करे,और सबसे महत्वपूर्ण समितियों में जारी अवैध वसूली के खिलाफ कार्रवाई करे,सरकार चाहे जितने विज्ञापन चलाए, जितने वीडियो जारी करे, लेकिन किसानों की असल पीड़ा को कभी दबाया नहीं जा सकता,खेत में खड़े किसान की सच्चाई, जनसंपर्क विभाग के कैमरे की मुस्कान से कहीं बड़ी होती है, छत्तीसगढ़ का किसान आज भी कह रहा है हम परेशान हैं,हमें मत छिपाओ,हमें सुनो।

## ऑनलाइन टोकनःऐप कम,यातना अधिक...

सरकार का दावा ऑनलाइन टोकन से किसानों को बड़ी सुविधा, किसानों का अनुभव ऐप चलना ही नहीं चाहता,और यदि गलती से खुल जाए तो खरीदी की सीमा कब की पूरी हो चुकी होती है,दूसरी तरफ ऑफलाइन टोकन की व्यवस्था भी भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है, किसानों के अनुसार टोकन काटने के नाम पर खुलेआम वसूली, पैसा दो, तभी बारी बने, कई वीडियो इसकी पुष्टि सोशल मीडिया में वायरल हैं।

## तौल में आधा किलो अतिरिक्त धान की जबरन वसूली

शासन के नियम के अनुसार, 40.700 किलो (ध्यान दें: 700 ग्राम बारदाने का वजन) प्रति बोरी निर्धारित है, परंतु समितियों में किसानों को 41.200 किलो तक धान तौलने को मजबूर किया जा रहा है, समिति कर्मचारियों का तर्क धान सूखती में कटौती हो जाएगी लेकिन विभागीय अधिकारियों के अनुसार कटौती की सीमा पहले से तय रहती है, यानि स्पष्ट रूप से अवैध धान वसूली।

# बालको ने मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन

-संवाददाता-

**कोरबा,12 दिसंबर 2025 (घटती-घटना)।**

वेदांता समूह की कंपनी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) ने जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, कोरबा के सहयोग से बालको अस्पताल में एक मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में बालको कर्मचारियों,व्यवसायिक साझेदारों उनके परिजनों और आसपास के समुदाय ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। 220 से अधिक रक्तदाताओं के सहयोग से ज़िले के ब्लड बैंक की क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। शिविर का उद्देश्य थैलेसीमिया, सिकल सेल डिज़ीज़,कैंसर,सड़क दुर्घटनाओं,मातृत्व संबंधी जटिलताओं तथा हीमोफीलिया जैसे रक्तस्रावजनित रोगों के लिए आवश्यक रक्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। साथ ही स्वैच्छिक रक्तदान और नियमित रक्तदान के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता भी बढ़ाई गई। सभी एकत्रित रक्त यूनिट्स का पूर्ण चिकित्सकीय परीक्षण के बाद उन्हें शासकीय मेडिकल कॉलेज, कोरबा के ब्लड बैंक में सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जाएगा, जहाँ से इन्हें ज़रूरतमंद मरीजों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। कंपनी की समुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराते हुए बालको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं निदेशक श्री राजेश कुमार ने कहा कि समुदाय को ज़रूरी स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराना हमारे विकास कार्यों की मुख्य प्राथमिकता है। कंपनी का मानना है कि स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि ही प्रगति की नींव हैं। ऐसे प्रयास उद्योग और समाज के साझा दायित्व को मजबूत बनाते हैं। इस शिविर में लोगों की बड़ी भागीदारी बताती है कि मिलकर किए गए प्रयास आपातकालीन स्थितियों में तैयारी को बढ़ाते हैं और ज़िले के ज़रूरतमंद मरीजों की मदद में महत्वपूर्ण साबित होते हैं। बालको की पहल की सराहना करते हुए जिला एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, कोरबा के नोडल अधिकारी डॉ. रविकांत सिंह राठौर ने कहा कि स्वैच्छिक रक्तदान आपातकालीन स्थितियों और दीर्घकालिक उपचार के लिए पर्याप्त रक्त भंडार बनाए रखने में अत्यंत जरूरी है। बालको के इस प्रयास ने बड़ी संख्या में लोगों को प्रेरित किया है। आज दान की गई प्रत्येक यूनिट किसी मरीज के लिए जीवनदायी सिद्ध होगी। सामुदायिक स्वास्थ्य के प्रति अपने निरंतर प्रयासों के तहत बालको वित्त वर्ष 2025 में 2 लाख से अधिक लोगों को विविध स्वास्थ्य सेवाओं से लाभान्वित किया है। प्रोजेक्ट आरोग्य के माध्यम से ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों, मातृ-शिशु स्वास्थ्य, पोषण और एचआईवी जागरूकता अभियानों द्वारा लगभग 76,000 लोगों तक प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएँ पहुँचाई गईं। मोबाइल हेल्थ वैन (एमएचवी) 70 से अधिक समुदायों में घर-घर स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान कर रही हैं, जिनसे 23,000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। वहीं, त्रैमासिक मेगा हेल्थ कैंप और जागरूकता कार्यक्रम टीकाकरण, स्वच्छता और निवारक स्वास्थ्य पर केंद्रित हैं। बालको मेडिकल सेंटर, 170-बेड की अत्याधुनिक कैंसर देखभाल सुविधा का प्रमुख केंद्र है जो 2018 से अब तक 60,000 से अधिक मरीजों की सेवा प्रदान कर चुका है। वहीं बालको अस्पताल, 120-बेड बहु-विशेषज्ञता वाला स्वास्थ्य केंद्र, 80 से ज्यादा मेडिकल विशेषज्ञों और 110 से अधिक सपोर्ट स्टाफ के सहयोग से प्रति वर्ष लगभग 1.8 लाख लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है।

# आश्रम में मादक द्रव्य पदार्थ के सेवन करते रंगे हाथ पकड़े गए अधीक्षक और कर्मचारी

-संवाददाता-

**कोरबा,12 दिसंबर 2025 (घटती-घटना)।**

कोरबा जिले के विकासखंड पोड़ी-उपरोड़ा स्थित प्राथमिक स्तर आदिवासी बालक आश्रम सरभोंका में अनुशासनहीनता का गंभीर मामला सामने आया है, जहाँ आश्रम परिसर में मादक द्रव्य पदार्थ के सेवन करते अधीक्षक और कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े गए।

जानकारी के अनुसार उक्त शिकायत की पुष्टि होने पर आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने कड़ा रुख अपनाते हुए दो कर्मचारियों को तत्काल निलंबित कर दिया, वहीं एक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी की सेवा समाप्त कर दी गई है। कार्यवाही पश्चात विभागीय कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा हैं की यहां पदस्थ अधीक्षक,दैनिक वेतन भोगी और कलेक्टर दर कर्मचारी के खिलाफ आश्रम परिसर में मादक द्रव्य पदार्थ का सेवन करने की शिकायत आदिवासी विकास विभाग को प्राप्त हुई थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए सहायक आयुक्त श्रीकांत कसेर ने नोडल अधीक्षक पोड़ी-उपरोड़ा को जांच के निर्देश दिए थे। निर्देशानुसार आश्रम का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अधीक्षक, दैनिक वेतन भोगी और कलेक्टर दर कर्मचारी मादक द्रव्य पदार्थ का सेवन कर नशे में धुत्त पाए गए। जांच में यह भी पुष्टि हुई कि तीनों कर्मचारी पूर्व में भी मादक द्रव्य पदार्थ का सेवन की आदत के लिए चिन्हित रहे हैं। गंभीर कदाचार को देखते हुए संबंधित विभाग ने त्वरित और सख्त कार्यवाही करते हुए दैनिक वेतन भोगी की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी हैं। वहीं, अधीक्षक को निलंबित कर मुख्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कोरबा में संलग्न किया गया है। कलेक्टर दर कर्मचारी को भी निलंबित करते हुए कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कोरबा में संलग्न किया गया है। संबंधित विभाग की इस सख्त कार्यवाही से महकमे में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों का कहना है कि आश्रम प्रणाली में अनुशासनहीनता किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और भविष्य में ऐसे मामलों पर और भी सख्त कार्यवाही की जाएगी।

**न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ0ग0)**

रा.प्र.क.- /ब-121/2025-26

**ईश्तहार**

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक संजय अग्रवाल आ0 आत्माराम अग्रवाल निवासी ब्रम्हरोड अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा ग्राम भगवानपुरकला स्थित खसरा नंबर 287 रकबा 0.020 हे0 भूमि एवं उस पर निर्मित मकान को अनावेदक सुलेखा जेसवाल पति राजकुमार जायसवाल निवासी अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 के पास अंकन राषि रूपये 40,00,000/- में बिक्री करने का सौदा तय कर बिक्री अनुमति हेतु आवेदन पत्र श्रीमान कलेक्टर महोदय सरगुजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो जांच एंव प्रतिवेदनार्थ इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।

उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 31.12.2025 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिषाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा।

आज दिनांक-01/12/2025 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील — तहसीलदार अम्बिकापुर सरगुजा

**आवश्यकता है**

दैनिक समाचार पत्र में कार्य करने हेतु निम्न पदों के लिए योग्य कर्मठ, जुझारू, महिला/पुरूष की आवश्यकता है।

| स.क्र. | पद | संख्या | वेतन |
|---|---|---|---|
| 01 | सह संपादक | 1 पद | 15,000 |
| 02 | समाचार संपादक | 1 पद | 15,000 |
| 03 | प्रबंध संपादक | 1 पद | 15,000 |
| 04 | विज्ञापन प्रभारी | 2 पद | 10,000 से 15,000 |
| 05 | ब्यूरो चीफ | 1 पद | 10,000 से 15,000 |
| 06 | संवाददाता | 2 पद | 8000 से 12,000 |
| 07 | कार्यालय सहायक | 1 पद | 7000 |

नोटः- आवेदक फोन पर संपर्क ना करें।
स्वयं बायोडाटा के साथ कार्यालय में संपर्क करें।

पता-कार्यालय दैनिक समाचार पत्र घटती-घटना शनि मंदिर के पास, नमनाकला, अम्बिकापुर छत्तीसगढ़,
मो.नं. - 9340154656, 98265-32611

# साहब...मेरे पास बैकुंठपुर जाने पैसे नहीं...

# सोनहत अस्पताल में सोनोग्राफी बंद

# महिला फूट-फूटकर रो पड़ी

अस्पताल की टूटी व्यवस्था पर उठे सवालः न सोनोग्राफी,न एक्स-रे, न जांच गरीब वनांचल बेहाल

सोनोग्राफी बंद होने की जानकारी मिलते ही रो पड़ी महिला कहा... 'अब कहां जाऊं साहब?'

बैकुंठपुर जाने तक के पैसे नहीं, बीमारी बढ़ने का डर,ग्रामीण सुविधाओं का सच उजागर

सोनहत अस्पताल में 3-4 महीने से बंद सोनोग्राफी, गर्भवती माताएं लौट रहीं बैरंग

एक्स-रे फिल्म भी खत्म, रिपोर्ट नहीं मिलती,आखिर किसने बिगाड़ी यह व्यवस्था?

लिपिड प्रोफाइल समेत कई जांच बंद,गांव के गरीब मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़...

## यूथ कांग्रेस का विरोध,15 दिनों में सुविधा चालू नहीं हुई तो होगा घेराव...

यूथ कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष प्रकाश चंद्र साहू ने एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी 15 दिनों में सोनोग्राफी और अन्य जांचें शुरू नहीं हुईं तो हजारों कार्यकर्ताओं के साथ स्वास्थ्य विभाग का घेराव होगा, ज्ञापन में निम्न मांगें शामिल थीं सोनोग्राफी सुविधा तत्काल चालू की जाए, एक्स-रे फिल्म और रिपोर्ट की समस्या दूर की जाए, लिपिड प्रोफाइल समेत सभी बंद जांच तत्काल शुरू हों, उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक गुलाब कमरो और सांसद के प्रयासों से सोनोग्राफी मशीन लगी थी, जिसका लाभ लोगों को मिलता था, लेकिन अब यह सुविधा पूरी तरह बंद है, जिससे जनता परेशान हो रही है।

-राजन पाण्डेय-

कोरिया,12 दिसंबर 2025 (घटती-घटना)।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनहत में मंगलवार को एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने वहां मौजूद हर व्यक्ति को कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध और भावुक कर दिया, रामगढ़ से सोनोग्राफी कराने आई एक महिला जैसे ही अस्पताल पहुंची,उसे पता चला कि यहां महीनों से सोनोग्राफी सुविधा बंद है,यह सुनते ही उसके चेहरे का दर्द और चिंता छलक पड़ी और उसकी आंखों से आंसू बह निकले, महिला ने भारी मन से कहा साहब...मेरे पास बैकुंठपुर जाने के पैसे भी नहीं हैं...अब क्या करूं? उसकी यह बात सुनकर वहां मौजूद लोग भी कुछ पल के लिए शांत हो गए, वनांचल क्षेत्र की गरीब महिलाओं के लिए सोनहत अस्पताल ही एकमात्र सस्ती और सुलभ जगह थी,पर अब वह भी बंद है।

## सोनहत में सोनोग्राफी सुविधा महीनों से ठप्प...गर्भवती महिलाएं लौट रहीं बैरंग

पूर्व में यहां सोनोग्राफी सुविधा शुरू होने से दूरदराज गांवों के गरीब लोगों को बड़ी राहत मिली थी, लेकिन अब कई महीनों से मशीनें बंद, गर्भवती महिलाएं जांच न होने से लौट जाती हैं, निजी अस्पतालों में महंगी जांच कराने मजबूरी, जनता में सरकार और प्रशासन के प्रति आक्रोश बढ़ा लोगों ने कहा जब सुविधा ही बंद रखनी थी तो इसे शुरू क्यों किया था?

## एक्स-रे फिल्म खत्म...रिपोर्ट नहीं...लिपिड प्रोफाइल सहित कई जांच बंद

सिर्फ़ सोनोग्राफी ही नहीं, बल्कि एक्स-रे फिल्म महीनों से खत्म, रिपोर्ट नहीं मिलती, लिपिड प्रोफाइल सहित कई आवश्यक जांच 4-5 महीने से बंद, यह स्थिति वनांचल के हजारों गरीब मरीजों के लिए स्वास्थ्य संकट बन चुकी है।

## नए बीएमओ को मिली चुनौती, लोगों को सुधार की उम्मीद...

सोनहत के नए बीएमओ डॉ. बलवंत सिंह को जनता उम्मीद की नजरों से देख रही है, डॉ. बलवंत पहले भी यहां सेवाएं दे चुके हैं और अच्छे चिकित्सक माने जाते हैं, लेकिन अस्पताल की वर्तमान अव्यवस्थित स्थिति उनके सामने बड़ी चुनौती रख रही है।

# अवैध धान परिवहन करते दो ट्रक पकड़े,कुल 1500 बोरी जब्त

**राजस्व एवं खाद्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई,वाहनों को थाना पटना में सुपुर्द**

-संवाददाता-

कोरिया,12 दिसंबर 2025 (घटती-घटना)।

राजस्व एवं खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से धान परिवहन कर रहे दो ट्रकों को पकड़ा है। पकड़े गए ट्रकों में एक में 800 बोरी तथा दूसरे में 700 बोरी, कुल 1500 बोरी (लगभग 600 क्विंटल) धान भरा हुआ पाया गया। जिला खाद्य अधिकारी श्री नटवर राठौर ने बताया कि ट्रक क्रमांक सीजी 04 एलजेड 6787 एवं सीजी 15 डीजे 3384 में इंडियन एग्रो राइस मिल, पटना से धान को बीएम फूड, अम्बिकापुर ले जाने का प्रयास किया जा रहा था। जब्त धान की अनुमानित कीमत करीब

18 लाख 60 हजार रुपए बताई जा रही है।जांच के दौरान दोनों ट्रकों के चालकों द्वारा कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके। इस पर अधिकारियों ने तत्काल धान जब्त करते हुए दोनों वाहनों को थाना पटना में विधिवत सुपुर्द कर दिया।

# महाविद्यालय में स्वदेशी संकल्प का संदेश,युवाओं को किया जागरूक

-संवाददाता-

कोरिया/सोनहत,12 दिसंबर 2025 (घटती-घटना)।

आत्मनिर्भर भारत-हर घर स्वदेशी,घर-घर स्वदेशी संकल्प अभियान के तहत सोनहत महाविद्यालय में आज एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया,कार्यक्रम में विद्यार्थियों को स्वदेशी उत्पादों के उपयोग, स्थानीय कारीगरों एवं उद्यमियों को प्रोत्साहन तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में योगदान के महत्व से अवगत कराया गया, कार्यक्रम प्रभारी एवं भाजपा मंडल महामंत्री मनोज साहू ने कहा कि स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग न केवल देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार और कुटीर उद्योगों को भी बढ़ावा देता है। उन्होंने विद्यार्थियों से स्वदेशी अपनाने का संकल्प लेने की अपील की, कार्यक्रम में भाजयुमो जिला मंत्री रमेश तिवारी, भाजयुमो उपाध्यक्ष दिलीप राजवाड़े,जयप्रकाश राजू साहू, महाविद्यालय के प्राचार्य, शिक्षक गण एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएँ उपस्थित रहे। 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' के समर्थन में चला हस्ताक्षर अभियान-सोनहत महाविद्यालय में आज एक राष्ट्र-एक चुनाव के समर्थन में व्यापक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। छात्रों को इस अवधारणा के लाभ,इसके क्रियान्वयन की आवश्यकता और इससे देश की लोकतांत्रिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभावों के बारे में जानकारी दी गई,कार्यक्रम के दौरान मनोज साहू ने कहा कि एक साथ चुनाव होने से चुनावी खर्च में उल्लेखनीय कमी आएगी, प्रशासनिक संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा, बार-बार लगने वाले आदर्श आचार संहिता से विकास कार्य बाधित नहीं होंगे, शासन-प्रशासन की निरंतरता बनी रहेगी अभियान में महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपने हस्ताक्षर कर इस पहल का समर्थन किया।

# बाल विवाह मुक्त भारत अभियान विद्यार्थियों को दी जा रही कानूनी जागरूकता

**बाल विवाह रोकने हेतु दिलाई गई शपथ**

-संवाददाता-

एमसीबी,12 दिसंबर 2025 (घटती-घटना)।

महिला एवं बाल विकास विभाग के नेतृत्व में संचालित बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत 100 दिवसीय विशेष जागरूकता कार्यक्रम जिलेभर में प्रभावी रूप से चलाया जा रहा है। जिला कलेक्टर डी.राहुल वेंकट के निर्देशानुसार एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी आदित्य शर्मा के मार्गदर्शन में जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में जन जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं।

इस क्रम में आईटीआई कॉलेज चिरमिरी, पॉलिटेक्निक कॉलेज चिरमिरी तथा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पोड़ी में छात्रों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। अधिकारियों ने बताया कि कानून के अनुसार लड़को के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 18 वर्ष अनिवार्य है। निर्धारित आयु से पूर्व विवाह करना एवं कराना

दोनों ही कानूनी अपराध हैं, जिसके लिए संबंधित व्यक्तियों पर कठोर कार्रवाई का प्रावधान है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित विद्यार्थियों को 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन), 181 (महिला हेल्पलाइन) और अन्य संरक्षण संबंधी सेवाओं की जानकारी दी गई। छात्रों को बाल विवाह की सूचना तुरंत संबंधित विभाग को देने और किसी भी बाल विवाह की घटना को रोकने में सहयोग प्रदान करने के लिए प्रेरित किया गया। अधिकारियों ने बताया कि बाल विवाह न केवल बच्चों के भविष्य और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है,बल्कि समाज में असमानता और हिंसा को भी बढ़ावा देता है। इसलिए प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वे बाल विवाह रोकने में प्रशासन का सहयोग करें और बाल संरक्षण संबंधी कानूनों के प्रति जागरूक रहें। इस जागरूकता कार्यक्रम के दौरान सभी विद्यार्थियों ने बाल विवाह न करने और न होने देने की शपथ ली। कार्यक्रम में आईटीआई कॉलेज के प्राचार्य श्री कमलेश्वर खलखो,शिक्षकगण,तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पोड़ी के प्राचार्य और शिक्षक व स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे।

**कैबिनेट मंत्री के गृह क्षेत्र में ही घटिया निर्माण! गौरव पथ सहित कई पंचायतों में लापरवाही उजागर**

# सीसी रोड व नाली निर्माण में खुली मनमानी, गुणवत्ता मानकों की उड़ रही धज्जियाँ

-राजेन्द्र शर्मा-

खड़गवां,12 दिसंबर 2025 (घटती-घटना)।

विभिन्न क्षेत्रों में सी सी रोड सह नाली निर्माण कार्य ठेकेदारों के द्वारा किया जा रहा है जो पूर्ण रूप से घटिया एवं गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य किया जा रहा है सी सी सड़क सह नाली निर्माण कार्य आर एम सी प्लांट का उपयोग कर सी सी सडक सह नाली निर्माण कार्य किया जाना है जो इस खड़गवां विकासखंड के निर्माणाधीन सी सी सड़कों में कहीं पर उपयोग नहीं किया जा रहा है और ओवर साइज गिट्टी का उपयोग और सड़क पर बिछाई जा रही प्लास्टिक भी जिस मापदंड की लगाई जानी है उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है सीमेंट की मात्रा भी कम उपयोग किया जा रहा है सड़क निर्माण कार्य।

क्षेत्र में ठेकेदारों के मुंशी के द्वारा मनमाने तरीके से सी सी सड़क सह

नाली का निर्माण कार्य कराया जा रहा है और कराया जाना है। जिसमें ग्राम पंचायत पेंड्री में गौरव पथ उधनापुर ग्राम पंचायत में गौरव पथ और खड़गवां ग्राम पंचायत के जनकपुर से महेंद्र घर तक निर्माण कार्य कराया जाना है।

इन सड़क निर्माण कार्य में भी फिर मजदूरों के सारे लाखों रुपए की सी सी सड़क सह नाली का निर्माण कार्य कराया जाएगा इन गौरव पथ सड़क निर्माण स्थल पर ना ही ठेकेदारों के द्वारा कोई इंजिनियर उपस्थित नहीं रहता है और ना ही विभागीय इंजिनियर निर्माण स्थल पर उपस्थित रहता है। फिर ठेकेदार के मुंशी मनमाने तरीके से बिना गुणवत्ता युक्त समाग्री के सी सी सडक निर्माण कार्य कराया जा रहा है?जबकि छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री के गृह ग्राम पंचायतों में एवं स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा स्वयं भूमिपूजन भी किया गया है और उसके बाद गौरव पथ से विभिन्न ग्राम पंचायतों में करोड़ों रुपए की लागत की सी सी सडक सह नाली निर्माण कार्य कराया जा रहा है वो बिना मापदंडों के जैसे आर एम सी प्लांट के और निर्माण कार्य की जो गुणवत्ता के तहत निर्माण कार्य किया जाना है वो किसी भी सी सी सड़क सह नाली निर्माण कार्य में नहीं किया जा रहा है अब सवाल ये उठता है कि जब छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री के गृह ग्राम के पंचायतों में गुणवत्ता एवं मापदंडों का पालन कर सी सी सडक सह नाली निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है तो अन्य क्षेत्रों में कितनी गुणवत्ता एवं मापदंडों से निर्माण कार्य कराया जा रहा होगा सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है?

CMYK

## छत्तीसगढ़ में साय सरकार के 2 साल पूरे होने पर अपने मंत्रियों के साथ कामकाज की रिपोर्ट पेश की

# हार से बौखला गई कांग्रेस : मुख्यमंत्री साय

### पेश किया 2 साल का रिपोर्ट कार्ड, कहा- सरेंडर नक्सलियों को ही मिलेगा घोषित इनाम

**रायपुर,12 दिसम्बर 2025।** छत्तीसगढ़ में साय सरकार के 2 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव अपने मंत्रियों के साथ सरकार के कामकाज की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने पुनर्वास नीति में बड़ा बदलाव किया है। अब सरेंडर करने वाले नक्सलियों को जमीन के साथ-साथ उनके ऊपर घोषित पूरा इनाम भी दिया जाएगा। पहले यह इनाम पुलिस को मिलता था, लेकिन नई नीति के तहत यह राशि सीधे आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को दी जाएगी। इससे पहले सीएम साय ने छत्तीसगढ़ में हो रहे विकास पर आधारित किताब का विमोचन किया। ये किताब स्थानीय गोंडी और हल्बी में भी पब्लिश की गई है। वहीं कांग्रेस ने शीतकालीन सत्र के पहले दिन का बहिष्कार किया है। इस पर सीएम साय ने कहा कि कांग्रेस हार से बौखला गई है। विधानसभा में हारे, लोकसभा में हारे, निगम चुनाव में हारे। हम चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत रहे। लेकिन ये उनका पर्सनल मैटर है।

#### बस्तर में उद्योग के लिए लोकल कारोबारियों को अलॉट होगी जमीन : साय

बस्तर में उद्योगों के लिए जमीन आवंटित की जा रही है, जिसमें स्थानीय कारोबारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार रोजगार देने वाले उद्योगपतियों को विशेष प्रोत्साहन भी दे रही है। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति को देश-विदेश में सराहा जा रहा है। नई नीति में रोजगार को सबसे महत्वपूर्ण रखा गया है, जिससे प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को बड़ा फायदा मिलने वाला है। सीएम साय ने कहा कि बस्तर में उद्योगों के लिए जमीन आवंटित की जा रही है, जिसमें स्थानीय कारोबारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार रोजगार देने वाले उद्योगपतियों को विशेष प्रोत्साहन भी दे रही है। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति को देश-विदेश में सराहा जा रहा है। नई नीति में रोजगार को सबसे महत्वपूर्ण रखा गया है, जिससे प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को बड़ा फायदा मिलने वाला है। कांग्रेस ने शीतकालीन सत्र के पहले दिन का बहिष्कार किया है। इस पर सीएम ने कहा कि कांग्रेस हार से बौखला गई है। विधानसभा में हारे, लोकसभा में हारे, निगम चुनाव में हारे। हम चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत रहे। लेकिन ये उनका पर्सनल मैटर है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पीएससी घोटाले की जांच की बात कही थी और अब सीबीआई इसकी जांच कर रही है। इसमें जो भी दोषी हैं, उन पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि पिछले दो साल में पीएससी की परीक्षा हुई है। उन्हें बहुत खुशी होती है जब गांव के किसान अपने सफल बेटा-बेटी के साथ मिलने आते हैं। बताते हैं कि सरकार और पीएससी पर उनका भरोसा बढ़ा है। इसी भरोसे के चलते लोग पीएससी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं।

#### सरेंडर नक्सलियों को सरकार देगी जमीन, इनाम भी नक्सलियों को मिलेगा : सीएम साय

राज्य सरकार ने पुनर्वास नीति में बड़ा बदलाव किया है। अब सरेंडर करने वाले नक्सलियों को जमीन के साथ-साथ उनके ऊपर घोषित पूरा इनाम भी दिया जाएगा। पहले यह इनाम पुलिस को मिलता था, लेकिन नई नीति के तहत यह राशि सीधे आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को दी जाएगी। राज्य सरकार ने पुनर्वास नीति में बड़ा बदलाव किया है। अब सरेंडर करने वाले नक्सलियों को जमीन के साथ-साथ उनके ऊपर घोषित पूरा इनाम भी दिया जाएगा। पहले यह इनाम पुलिस को मिलता था, लेकिन नई नीति के तहत यह राशि सीधे आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को दी जाएगी।

#### सीएम साय के साथ कैबिनेट मंत्री भी मौजूद

छत्तीसगढ़ में साय सरकार के दो साल पूरे होने पर सीएम विष्णुदेव साय अपने मंत्रीमंडल के साथ कामकाज का लेखा-जोखा पेश कर रहे हैं।

#### नई उद्योग नीति : 8 लाख करोड़ से ज्यादा का मिल चुका बिजनेस

सीएम साय ने कहा...राजधानी रायपुर,बिरगांव आदि को लेकर नया प्रोजेक्ट बनाकर हम काम कर रहे। पिछले साल हमारी सरकार जीएसटी कलेक्शन में नंबर रहा था। हमारी सरकार ने नई उद्योग नीति बनाई है। इसकी सराहना पूरे देश में हो रही है। 8 लाख करोड़ से ज्यादा का बिजनेस छत्तीसगढ़ को मिल चुका है। नई उद्योग नीति का लाभ हमको मिल रहा है। अभी तक 10 से 12 हजार लोगों को नौकरी दे चुके हैं। शिक्षा विभाग में तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, रायपुर में एयर कार्गो की सुविधा शुरू हुई है। हम लोग अपने मंत्रालय में ई-ऑफिस प्रणाली लागू किए हैं। डिजिटल व्यवस्था को भी हमने शुरू किया है।

#### दूसरे राज्य और देश के कारोबारियों को आकर्षित किया

अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार की नीतियों और नियमों में दूसरे राज्य और देश के कारोबारियों को आकर्षित किया है और बड़े पैमाने में प्रदेश में निवेश आया है। सरकार ने नक्सल मुद्दे को गंभीरता से लिया और अभियान चलाकर नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ की घोषणा करने की तैयारी कर रहे हैं। प्रदेश की नई औद्योगिक नीति में डिफेंस,आईटी,एआई और ग्रीन एनर्जी जैसे उभरते क्षेत्रों को विशेष पैकेज दिया गया है। बस्तर और सरगुजा में उद्योग लगाने वालों को विशेष रियायतें, सस्ती जमीन और टैक्स लाभ दिए जा रहे हैं। पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिलने के बाद होम-स्टे पॉलिसी और ईको-टूरिज्म पर तेजी से काम शुरू हुआ है।

# छत्तीसगढ़ के सुकमा में 33 लाख के 10 इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण....

**सुकमा, 12 दिसम्बर 2025।** छत्तीसगढ़ के सुकमा में पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज के समक्ष शुक्रवार को 33 लाख के इनामी 10 नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। इस अवसा पर डीआईजी सीआरपीएफ आनंद सिंह कलेक्टर देवेश ध्रुव, एसपी किरण चव्हाण,पुलिस अधीक्षक सुकमा,सर्व आदिवासी पदाधिकारी सहित समाज-प्रमुखों,पुलिस अधिकारियों और बड़ी संख्या में जवान उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ शासन एवं भारत सरकार की मंशा के अनुरूप स्थानीय समाज,पुलिस, स्थानीय प्रशासन तथा सुरक्षा बल–क्षेत्र में शांति स्थापित करने,पुनर्वास सुनिश्चित करने और समावेशी विकास को आगे बढ़ाने की दिशा में आज जिला सुकमा में एक महत्त्वपूर्ण सफलता मिली। 'पूना मारगेम : पुनर्वास से पुनर्जीवन' पहल के अंतर्गत आज जिला सुकमा में कुल 10 माओवादी कैडर, जिनमें 06 महिला माओवादी भी शामिल हैं और उन पर कुल 33 लाख का इनाम घोषित है। उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़कर सामाजिक मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया। इन आत्मसमर्पित कैडरों ने एक एके-47,दो एसएलआर राइफलें,01 स्टेन गन, 01 बीजीएल लॉन्चर भी सुरक्षा बलों के समक्ष विधिवत रूप से सौंपे हैं। इनन हथियारों को

जमा करने पर कुल 08 लाख का इनाम घोषित था। 'पूना मारगेम : पुनर्वास से पुनर्जीवन स्थायी शांति और सकारात्मक बदलाव की दिशा में एक और महत्त्वपूर्ण कदम है। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुन्दरराज पी ने कहा कि 'जिला सुकमा में 10 माओवादी कैडरों का पुनर्वास यह दर्शाता है कि हिंसक और जनविरोधी माओवादी विचारधारा का अंत अब निकट है। लोग 'पूना मारगेम : पुनर्वास से पुनर्जीवन' पहल पर भरोसा जताते हुए शांति, गरिमा और स्थायी प्रगति का मार्ग चुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन, भारत सरकार, बस्तर पुलिस, स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बल–क्षेत्र में शांति स्थापित करने,पुनर्वास सुनिश्चित करने और समावेशी विकास को आगे बढ़ाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं।' उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि पिछले 11 महीनों में बस्तर रेंज में 1514 से अधिक माओवादी कैडरों ने हिंसा का मार्ग छोड़कर सामाजिक मुख्यधारा से जुड़ने का निर्णय लिया है। बस्तर आईजी ने कहा,'शेष माओवादी कैडर जिनमें Politburo सदस्य देवजी, डीकेएसजेडसी सदस्य पाप्पा राव,देवा (बारसे देवा) तथा अन्य शामिल हैं,उनके पास हिंसा त्यागकर मुख्यधारा में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। 'पुलिस अधीक्षक सुकमा किरण चव्हाण ने बताया कि 10 सक्रिय माओवादियों द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में जिले में कुल 263 माओवादी कैडर हिंसा त्यागकर मुख्यधारा में शामिल हो चुके हैं। यह आँकड़ा बताता है कि क्षेत्र में विश्वास, शांति और विकास की प्रक्रिया लगातार गति पकड़ रही है। यह उल्लेखनीय है,'पूना मारगमः पुनर्वास से सामाजिक पुनर्समावेशन' पहल के तहत आज वायान वाटिका, सुकमा में एक महत्वपूर्ण और प्रतीकात्मक कार्यक्रम आयोजित किया गया,जिसमें आज मुख्यधारा में शामिल हुए 10 माओवादी कैडरों ने वे पौधे रोपे, जिन्हें समुदाय के वरिष्ठजनों ने पुनर्समावेशन के प्रतीक के रूप में उन्हें प्रदान किया था।

जिला सुकमा में स्थानीय समुदाय के वरिष्ठजनों की उपस्थिति में पुनर्वासित माओवादी कैडरों द्वारा किए गए पौधारोपण ने आशा और शांतिपूर्ण भविष्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का एक सशक्त प्रतीक प्रस्तुत किया। सुकमा जिला मुख्यालय स्थित पुनर्वास केंद्र के पौधरोपण स्थल का नाम 'वायान वाटिका' रखा गया है, जिसका अर्थ स्थानीय आदिवासी गोंडी भाषा में 'आशा और भविष्य की बगिया' होता है।

# छत्तीसगढ़-आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर बस घाटी में गिरी,9 यात्रियों की मौत

**जगदलपुर,12 दिसम्बर 2025।** छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की सीमा पर शुक्रवार सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया। मारेडमिल्ली थाना क्षेत्र स्थित घाटी में एक यात्री बस अनियंत्रित होकर नीचे गिर पड़ी। हादसे में 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को तत्काल भद्राचलम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। प्रशासन ने मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई है।

#### कैसे हुआ हादसा?

जानकारी के अनुसार, 12 दिसंबर की सुबह अरकू से रायलासीमा चिंटूर की ओर जा रही यह यात्री बस चिंटूर-भद्राचलम घाट रोड पर पहुंची ही थी कि चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा। बस तेजी से घाटी में नीचे गिर गई और घनी झाड़ियों में जाकर उलट गई। बस में कुल 40 यात्री सवार थे। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो और तस्वीरों में सड़क पर बिखरे शव, यात्रियों का सामान और क्षतिग्रस्त बस साफ दिखाई दे रही है। कई यात्री बस से उछलकर सड़क पर जा गिरे।

#### स्थानीय लोग बने फ़र्स्ट रेस्पॉन्डर

हादसे के तुरंत बाद मार्ग से गुजर रहे वाहन चालकों और ग्रामीणों ने अपनी जान जोखिम में डालकर रेस्क्यू शुरू किया। कई घायलों को अपनी गाड़ियों में बैठाकर अस्पताल पहुंचाया गया। इस दौरान सड़क पर अफरा-तफरी मच गई।

#### प्रशासन की प्रतिक्रिया

एएसआर जिला कलेक्टर दिनेश कुमार ने बताया कि बस दुर्घटना चिंटूरू और भद्राचलम के बीच घाट रोड पर हुई। सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम और पुलिस मौके पर पहुंच गई। बचावकर्मी बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने में जुटे रहे। कलेक्टर ने कहा कि मृतकों और घायलों की पहचान की प्रक्रिया जारी है।

#### पृष्ठभूमि और आगे की स्थिति

चिंटूर-भद्राचलम घाट रोड पर पहाड़ी मोड़ों और खड़ी ढलानों के कारण दुर्घटनाएं अक्सर होती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर सुरक्षा बैरियर और संकेतक पर्याप्त नहीं हैं। अधिकारियों ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं और बस के अनियंत्रित होने के कारणों का पता लगाया जा रहा है।

# अवैध कोल वसूली मामले में राकेश जैन गिरफ्तार

### कोल घोटाले के मास्टरमाइंड सूर्यकांत को हवाला के जरिए 50 करोड़ भेजा; 19 दिसंबर तक पुलिस रिमांड

**रायपुर,12 दिसम्बर 2025।** छत्तीसगढ़ अवैध कोल वसूली के मामले में राकेश कुमार जैन को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी अवैध कोल वसूली को फर्जी कंपनियों और हवाला के जरिए कोल घोटाले के आरोपियों तक पहुंचाता था। आरोपी पिछले 5 साल से फरार था और उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। जैन को रायपुर कोर्ट से ईओडब्ल्यू की टीम ने गिरफ्तार किया। यहां उसे स्पेशल कोर्ट में न्यायधीश नीरज शर्मा के सामने पेश किया गया। कोर्ट ने जैन को आठ दिन यानी 19 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी पेशे से ष्ट है और लोगों को शेयर मार्केट में निवेश कर मुनाफे का झांसा देकर शातिराना ढंग ठगी करता था। जैन के खिलाफ ईओडब्ल्यू सहित अन्य थानों 16 से ज्यादा मामलों में एफआईआर दर्ज है।

#### हवाला के जरिए करोड़ों की अवैध कोल वसूली

जांच में पता चला है कि आरोपी ने फर्जी कंपनियों का जाल बिछाकर करोड़ों रुपये की अवैध कोल वसूली की। वह इस पैसे को हवाला के जरिए कोल घोटाले के मुख्य आरोपियों तक भेजता था और बदले में कमीशन लेता था। लगभग 50 करोड़ रुपये को फर्जी खर्च दिखाकर नकद बनाया गया और कोल वसूली के मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी तक पहुंचाया गया। जांच में यह भी सामने आया कि राकेश कुमार जैन ने शराब मामले के आरोपी अनवर ढेबर के लिए भी घोटाले की रकम को पक्के में बदलने का काम किया। इसके लिए उसने एंट्री और फर्जी दस्तावेज़ का इस्तेमाल किया। आरोपी जैन ने अपने और अपने साले के नाम पर दर्जन भर से अधिक कंपनियां बनाई, जिनके जरिए यह सभी अवैध काम किए गए।

# घर के सेप्टिक टैंक में मिली नवविवाहिता की लाश तेज बदबू आने पर हुआ खुलासा... 4 माह से लापता थी

**कवर्धा,12 दिसम्बर 2025।** छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के सहसपुर लोहारा थाना अंतर्गत बांधाटोला गांव में गुरुवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। गांव में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक घर के सेप्टिक टैंक से उठ रही तेज दुर्गंध के बाद पुलिस द्वारा की गई जांच में एक नवविवाहिता का शव बरामद किया गया। मृतका की पहचान कामिनी निषाद के रूप में हुई है, जो पिछले लगभग चार महीनों से लापता थी और जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज थी।

**तेज बदबू ने खोला राज, ग्रामीणों ने दी सूचना :** गुरुवार दोपहर घर के सेप्टिक टैंक से अचानक असामान्य रूप से तेज दुर्गंध फैलने लगी। बदबू इतनी तीव्र हो गई कि आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। स्थिति संदिग्ध देख ग्रामीणों ने पति और परिजनों

से पूछताछ की,लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने पर मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। थाना सहसपुर लोहारा से पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। जब टैंक को खुलवाकर अंदर देखा गया, तो उसमें एक महिला का शव दिखाई दिया। ग्रामीणों और पुलिस की मदद से शव को बाहर निकाला गया। शव अत्यधिक सड़-गल चुका था, जिससे स्पष्ट था कि मृत्यु को काफी समय बीत चुका था।

**लव मैरिज के दो महीने बाद गायब हुई थी कामिनी :** जानकारी के अनुसार, कामिनी ने जुलाई 2025 में भोजराज पटेल से प्रेम विवाह किया था। बताया जा रहा है कि भोजराज के परिवारजनों को यह विवाह रास नहीं आया था। शादी के लगभग दो महीने बाद यानी सितंबर में कामिनी अचानक गायब हो गई। पति भोजराज ने उसे ढूंढ़ने का प्रयास भी किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। अंततः उसने 7 नवंबर को पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस तभी से खोजबीन कर रही थी, लेकिन कोई ठोस जानकारी हाथ नहीं लगी।

**ससुर पर ग्रामीणों का शक, पूरा परिवार हिरासत में :** शव बरामद होने के बाद ग्रामीणों ने मृतका के ससुर जहर पटेल पर हत्या का संदेह जताया है। वहीं पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए ससुराल पक्ष के सभी सदस्यों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस किसी भी संभावना से इंकार नहीं कर रही है और सभी पहलुओं पर बारीकी से जांच कर रही है। एडिशनल एसपी पुष्पेंद्र सिंह बघेल ने बताया कि शव काफी डिकंपोज हो चुका है, इसलिए मौत का सटीक कारण पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही बताया जा सकेगा।

# डीएसपी कल्पना शर्मा को लेकर चर्चा में आए दीपक टंडन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

**रायपुर,12 दिसम्बर 2025।** डीएसपी कल्पना शर्मा पर गंभीर आरोप लगाने वाले दीपक टंडन के कारनामे अब सामने आने लगे हैं। इसी बीच खबर है कि 420 के आरोपी दीपक टंडन उर्फ अंबेडकर टंडन के खिलाफ कोरबा की एक कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। आपको बता दें कि आरोपी दीपक टंडन उर्फ अंबेडकर टंडन वहीं आरोपी है जिसने डीएसपी कल्पना वर्मा को करीब 2 करोड़ रुपए के गिफ्ट और प्यार में झांसा देने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। जानकारी के मुताबिक उनकी पत्नी बरखा टंडन के खिलाफ डीएसपी कल्पना वर्मा के पिता ने 40 लाख रुपए के लेन-देन फ्रॉड के आरोप लगे और ये मामले कोर्ट में लंबित है,इसी बीच दीपक टंडन ने तमाम स्क्रीन शार्ट और कथित वीडियो पत्रकारों को उपलब्ध कराएं। सूत्रों के मुताबिक कोरबा की जिस कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है वहां आज 12 दिसंबर को आरोपी दीपक टंडन उर्फ अंबेडकर टंडन को पेश होना है। ये गिरफ्तारी वारंट न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा, जिला कोरबा कु. रंजू वैष्णव की कोर्ट द्वारा जारी किया गया है।

# पंचायत से लेकर जिला स्तर के सभी विभागों में भी ई-ऑफिस प्रणाली लागू

**रायपुर,12 दिसम्बर 2025।** छत्तीसगढ़ सरकार ने ई-ऑफिस के माध्यम से काम करने के लिए सभी विभागों, संभागायुक्त और सभी कलेक्टरों को दिशा निर्देश जारी किया है। बता दें कि सुशासन की दिशा में काम करते हुए सरकार ने प्रदेश में शासकीय कार्य को अधिक प्रभावी, सरलीकृत, उत्तरदायी और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से मंत्रालय,विभागाध्यक्ष और जिले स्तर पर ई-ऑफिस प्रारंभ किया है। मंत्रालय के सभी विभागों और राज्य के विभिन्न कार्यालयों में ई-ऑफिस के माध्यम से नस्ती और डाक का संपादन किया जा रहा है। एक जनवरी 2026 से सभी विभागाध्यक्ष, संभाग आयुक्त और कलेक्टर कार्यालय में संपूर्ण कार्यालयीन नस्ती और डाक का संपादन ई-ऑफिस के माध्यम से ही किया जाए। विभाग प्रमुख के अनुमोदन के बिना कोई भी फिजिकल फाइल संचालित नहीं किया जाए। ऐसे प्रकरण जिस पर शासन स्तर पर सहमति या अनुमोदन की

आवश्यकता हो उसे अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा ई-ऑफिस के फाइल के माध्यम से ही शासन को प्रेषित किया जाए। सूचनात्मक पत्राचार ई-ऑफिस के रिसीप्ट के माध्यम से किया जाए। अधिकारियों द्वारा शासकीय प्रवास के दौरान मुख्यालय से अन्यत्र भी ई-ऑफिस के माध्यम से कार्य संपादित किया जाए। सार्वजनिक अवकाश अवधि में शासकीय सेवक ई-ऑफिस के माध्यम आवश्यकतानुसार कार्य संपादित कर सकते हैं। यथासंभव दस्तावेज को Digitally Generate किया जाए।

## कैबिनेट ने दी तीन फैसलों को मंजूरी,पहली बार डिजिटली होगा सेंसस

# एक व्यक्ति की जनगणना पर 97 रुपए खर्च आएगा केंद्र ने जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ मंजूर किए

**नई दिल्ली,12 दिसम्बर 2025।** कैबिनेट ने शुक्रवार को तीन महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी। कैबिनेट ने जनगणना के लिए 11,718 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोयला लिंकेज नीति में सुधार के लिए कोलसेटू नीति को भी मंजूरी दी है। सरकार ने खोपरा 2025 सीजन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को भी नीतिगत मंजूरी दे दी है।

### जनगणना 2027 के बारे में केंद्रीय मंत्री ने बताया

कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जनगणना 2027 की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि विश्व का सबसे बड़ा प्रशासनिक और सांख्यिकीय अभ्यास होगा। जनगणना 2027 अब तक की 16 वीं और स्वतंत्रता के बाद की 8 वीं जनगणना होगी। जनगणना केंद्र का विषय है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश में जनगणना अधिनियम, 1948 और जनगणना नियम, 1990 के तहत इसे किया जाता है। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। कोविड महामारी के कारण जनगणना 2021 आयोजित नहीं की जा सकी। इससे पहले 16 जून 2025 को जनगणना 2027 की राजपत्र अधिसूचना जारी की गई। जनगणना 2027 की अनुमानित लागत 11,718 करोड़ रुपये होगी।

### दो चरणों में होगी जनगणना

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि जनगणना की संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 को होगी। बर्फ से ढके क्षेत्रों के लिए यह तिथि 1 अक्टूबर 2026 को होगी। वैष्णव ने कहा, 'जनगणना 2027 दो चरणों में आयोजित की जाएगी। पहले चरण में मकान सूचीकरण और आवास जनगणना होगी। इसे अप्रैल से सितंबर 2026 तक अंजाम दिया जाएगा। दूसरे चरण में जनसंख्या की गिनती होगी। यह फरवरी 2027 से शुरू होगी। बर्फ से ढके क्षेत्रों में सितंबर 2026 से शुरू होगी।

### 30 लाख लोग जनगणना को देंगे अंजाम

कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री ने बताया कि जाति गणना को भी जनगणना 2027 में शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस बार स्व-गणना का भी विकल्प प्रदान किया जाएगा। जनगणना-एक-सेवा विभिन्न मंत्रालयों/राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों को उपयोगकर्ता के अनुकूल, मशीन-पठनीय और कार्रवाई योग्य प्रारूप में डैशबोर्ड जैसी सुविधाओं के साथ डेटा उपलब्ध कराएगी। जनगणना के दौरान राष्ट्रव्यापी जागरूकता,सम्मावेशी भागीदारी,अंतिम छोर तक जुड़ाव और जमीनी कार्यों के समर्थन के लिए लक्षित और व्यापक प्रचार अभियान चलाया जाएगा। इस कार्य में लगभग 30 लाख जमीनी कार्यकर्ता शामिल होंगे और 1.02 करोड़ मानव-दिवस का रोजगार सृजित होगा।

### मनरेगा की जगह पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी होगा नया नाम

मनरेगा योजना अब पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी के नाम से जाना जाएगा। मोदी सरकार की कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय हो गया है। ग्रामीणों को साल में 125 दिन काम की गारंटी मिलेगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस आशय की जानकारी दी। शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में सरकार ने इसके लिए 1.51 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। मनरेगा योजना को साल 2005 में तत्कालीन मनमोहन सरकार ने शुरुआत की थी। शुरु में इसका नाम नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था, बाद में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट (मनरेगा) किया गया था। यह योजना देश के ग्रामीण परिवारों को आर्थिक स्थिरता और आजीविका देने वाले सबसे बड़े सरकारी फ्लैगशिप योजनाओं में से एक है। पूरी योजना का संचालन ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से किया जाता है।

## लगातार विवादास्पद बयान दे रहे आईएएस संतोष वर्मा को सरकार ने सभी पदों से हटाया

### बर्खास्तगी का भेजा जाएगा प्रस्ताव...

**मध्य प्रदेश,12 दिसम्बर 2025।** मध्य प्रदेश के आईएएस अफसर संतोष वर्मा एक के बाद एक विवादास्पद बयान दे रहे हैं। ब्राह्मण बेटियों को लेकर असभ्य बयान देने वाले आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ सरकार ने कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश दिए हैं कि वर्मा को सेवा से बर्खास्त करने के लिए प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाए। जानकारी के मुताबिक़,मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने विवादिन बयानों वाले आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के मामले को संज्ञान लेते हुए सामान्य प्रशासन विभाग को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सामान्य प्रशासन विभाग ने आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा को सभी पदों से हटा दिया है। संतोष वर्मा को कृषि विभाग के उप सचिव पद से हटाया गया। उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग में पदस्थ करते हुए तत्काल प्रभाव से एक पक्षीय कार्यमुक्त करने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही आईएएस संतोष वर्मा के ख़िलाफ़ बर्खास्ती की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। संतोष वर्मा को केंद्र सरकार से भारतीय प्रशासनिक सेवा से बर्खास्त करने की सिफारिश की गयी है।

### सीएम मोहन यादव ने क्या कहा...?

इस संबंध में देर रात मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आधिकारिक बयान जारी किया है,जिसमें कहा गया है,राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिये पदोन्नति,फर्जी और जाली आदेश तैयार करके ली गई है। विभिन्न न्यायालय में आपराधिक प्रकरण लंबित है। फर्जी दस्तावेजों और धोखाधड़ी के आधार पर ली गई आईएएस की पदोन्नति गलत है। अतः आई ए एस से बर्खास्त करने का प्रस्ताव केन्द्र शासन को प्रेषित किया जा रहा है। वर्मा के विरूद्ध जाली और फर्जी दस्तावेज के आधार पर संनिष्ठा प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के आरोप के लिये विभागीय जांच अंतिम स्तर पर है। वर्तमान प्रकरण में संतोष वर्मा द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का प्रस्तुत जबाव संतोषजनक नहीं है। उनके द्वारा सतत मर्यादा विहीन वक्तव्य जारी किये जा रहे हैं। अतः उन्हें चार्जशीट जारी करने का निर्णय लिया गया। राज्य शासन द्वारा वर्मा को उप सचिव, कृषि विभाग से हटाकर जीएडी पूल में बिना विभाग और बिना कार्य के अटैच करने का निर्णय लिया गया है।

### इस तरह दिया विवादित बयान

दरअसल,वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और अनुसूचित जाति-जनजाति अधिकारी-कर्मचारी संघ (अजाक्स) के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष संतोष वर्मा ने 23 नवंबर को बेहद ही विवादित बयान दिया आईएएस संतोष वर्मा ने भोपाल के सेकेंड स्टॉप स्थित अंबेडकर मैदान में आयोजित अनुसूचित जाति-जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रांतीय अधिवेशन में प्रांताध्यक्ष का पदभार संभालते हुए आरक्षण पर बयान दिया. उन्होंने कहा, 'जब तक कोई ब्राह्मण अपनी बेटी मेरे बेटे को दान नहीं करता या उससे संबंध नहीं बनाता, तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए।

## पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का निधन,90 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस

**नई दिल्ली,12 दिसम्बर 2025।** कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का शुक्रवार सुबह लातूर में निधन हो गया। 90 वर्षीय पाटिल ने सुबह करीब 6:30 बजे अपने आवास पर अंतिम सांस ली। वह लंबे समय से अस्वस्थ थे और घर पर ही उपचार चल रहा था। उनके निधन से महाराष्ट्र सहित राष्ट्रीय राजनीति में शोक की लहर है। शांत, संयत और कार्यकुशल नेतृत्व के लिए वे भारतीय राजनीति में विशिष्ट पहचान रखते थे। शिवराज पाटिल का जन्म 12 अक्टूबर 1935 को लातूर जिले के चाकुर में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने आयुर्वेद का अध्ययन किया और फिर मुंबई विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई पूरी की। उनका राजनीतिक सफर 1967 में लातूर नगर पालिका से शुरू हुआ,जो आगे चलकर एक लंबी और प्रभावशाली राजनीतिक यात्रा में बदल गया। 1980 में वे पहली बार लातूर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए और इसके बाद सात बार इस सीट से जीत दर्ज की। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के कार्यकाल में पाटिल ने रक्षा,वाणिज्य,विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी,परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और अंतरिक्ष जैसे कई महत्वपूर्ण विभागों में राज्य मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली। 1991 से 1996 तक वे लोकसभा अध्यक्ष रहे। अपने कार्यकाल के दौरान लोकसभा के आधुनिकीकरण, कंप्यूटरीकरण, कार्यवाही के सीधा प्रसारण और नई लाइब्रेरी भवन के निर्माण जैसे कई महत्त्वपूर्ण बदलावों को गति दी, जिसे संसदीय सुधारों का अहम दौर माना जाता है। 2004 में लोकसभा चुनाव हारने के बावजूद उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री बनाया गया। हालांकि 2008 मुंबई आतंकी हमलों के बाद उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद पाटिल को पंजाब का राज्यपाल और चंडीगढ़ का प्रशासक नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने 2010 से 2015 तक सेवाएं दीं। शिवराज पाटिल को एक शांत, विचारशील और सिद्धांतवादी राजनेता के रूप में हमेशा याद किया जाएगा।

## यूपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान 14 दिसंबर को,नामांकन की तारीख आई सामने

**लखनऊ,12 दिसम्बर 2025।** उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव का शेड्यूल घोषित कर दिया गया है। पार्टी ने लखनऊ से जारी पत्र में चुनाव प्रक्रिया और समय-सीमा की पूरी जानकारी दी है। लंबे समय से यूपी बीजेपी कार्यकर्ताओं को जिस पल का इंतजार था, वह अब आ गया है। 13 दिसंबर को लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक अध्यक्ष पद के लिए नामांकन प्रक्रिया होगी, जबकि 14 दिसंबर को यूपी बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। मौजूदा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है। सूत्रों के अनुसार नए प्रदेश अध्यक्ष के चयन में जातिगत समीकरण, बीजेपी के वोटबैंक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ तालमेल को प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य इकाई ने हाईकमान को छह नेताओं के नाम भेजे हैं, जिनमें दो ब्राह्मण, दो ओबीसी और दो दलित नेता शामिल हैं। पार्टी नेतृत्व जल्द ही संतुलन बनाते हुए किसी एक नाम पर निर्णय लेगा। राज्य में अध्यक्ष पद के लिए तीन प्रमुख नाम चर्चा में हैं। ब्राह्मण उम्मीदवार हरीश द्विवेदी लंबे समय तक संगठन में सक्रिय रह चुके हैं और वर्तमान में असम में पार्टी के इंचार्ज हैं। ओबीसी उम्मीदवारों में बीएल वर्मा और धर्मपाल सिंह के नाम प्रमुख हैं।

## कफ सिरप मामले में यूपी के कई जिलों में ईडी का छापा

**लखनऊ,12 दिसम्बर 2025।** उत्तर प्रदेश में अवैध कफ सिरप बिक्री मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार सुबह उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर और सहारनपुर सहित कई अन्य ठिकानों पर छापा मारा है। इसके अलावा गुजरात और झारखंड सहित कई राज्यों में 25 से अधिक ठिकानों पर भी ईडी ने छापा मारा है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही है। लखनऊ में ईडी ने सिपाही आलोक सिंह की कोठी पर छापा मारा है। खबर लिखे जाने तक ईडी के अधिकारी दस्तावेजों के अलावा पूरी कोठी में छानबीन कर रही है।

## राहुल गांधी ने संसद में प्रदूषण के मुद्दे पर व्यापक चर्चा की मांग की

# सरकार प्रदूषण रोकने का प्लान बनाए : राहुल गांधी

**नई दिल्ली,12 दिसम्बर 2025।** कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को लोकसभा में वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, 'हमारे देश के ज्यादातर बड़े शहर जहरीली हवा की चपेट में हैं। लाखों बच्चे फेफड़ों की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। लोग कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं।' राहुल ने कहा, 'यह एक अहम मुद्दा है। मुझे पूरा यकीन है कि सरकार और हमारे बीच इस मामले पर एक सहमति होगी। इस सदन में मौजूद हर सदस्य इस बात से सहमत होगा कि प्रदूषण के कारण देश के लोगों को जो नुकसान हो रहा है, उस पर हम सभी मिलकर काम करना चाहेंगे।' इसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा...सरकार ने पहले दिन से ही अपना रुख साफ कर दिया था कि हम सभी अहम मामलों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। सरकार कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टी के नेताओं से सुझाव लेने के लिए भी तैयार है। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने तमिलनाडु में दीपक जलाने की मांग पर हिंदुओं पर लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया। उन्होंने तमिलनाडु की ष्ठख्व सरकार पर निशाना साधते हुए कहा- तमिलनाडु सनातन धर्म के विरोध का प्रतीक बन गया है। उनके मंत्री सनातन धर्म के विरुद्ध बयान देते हैं।

**राहुल ने कांग्रेस सांसदों से संसद में पार्टी परफॉर्मेंस पर चर्चा की :** राहुल गांधी ने शुक्रवार को संसद भवन के एनेक्स एक्सटेंशन बिल्डिंग में कांग्रेस सांसदों के साथ बैठक की। इसमें संसद के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस सांसदों के परफॉर्मेंस की समीक्षा हुई। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल के निधन पर शोक प्रस्ताव भी पारित किया गया। कांग्रेस की इस मीटिंग में पार्टी के सभी दिग्गज सांसद पहुंचे,लेकिन केरल से पार्टी के सांसद शशि थरूर शामिल नहीं हुए। इससे पहले 30 नवंबर को कांग्रेस की एक स्ट्रैटजिक मीटिंग में भी थरूर शामिल नहीं हुए थे। तब थरूर ने अपनी सफाई में कहा था कि वे अपनी 90 साल की मां के साथ थे।

**कांग्रेस सांसदों ने शिवराज पाटिल के सम्मान में शोक प्रस्ताव पारित किया :** कांग्रेस सांसदों ने राहुल गांधी की अध्यक्षता वाली बैठक में पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक प्रस्ताव पारित किया। सीनियर कांग्रेस नेता शिवराज का शुक्रवार को 90 की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने लातूर में सुबह 6.30 बजे अंतिम सांस ली। शिवराज पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान 1 दिसंबर से अब तक 3 बिल लोकसभा में पास हुए हैं।

### राहुल बोले...एकदूसरे पर दोषारोपण के बजाय,जनता के बारे में बात करते हैं...

राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा...मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि हम चर्चा को इस बात पर केंद्रित न करें कि हम क्या नहीं कर पाए और आप क्या नहीं कर पाए, बल्कि सीधे इस बात पर ध्यान दें कि हम भविष्य में भारत की जनता के लिए क्या करने जा रहे हैं, हमें कौन से कदम उठाने होंगे। राहुल ने कहा...मेरा मानना है कि हम एक-दूसरे पर दोषारोपण करने के बजाय,इस एक मुद्दे पर (प्रदूषण), जिस पर हम सहमत हैं, कोई असहमति नहीं है, चर्चा करें। चलिए, भारत की जनता के भविष्य के बारे में बात करते हैं।

### लाखों बच्चे फेफड़ों की बीमारियों से ग्रसित हो रहे...

राहुल ने कहा...'हमारे ज्यादातर बड़े शहर जहरीली हवा की चादर के नीचे जी रहे हैं। लाखों बच्चे फेफड़ों की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। उनका भविष्य नष्ट हो रहा है। लोग कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। बुजुर्गों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। यह एक अहम मुद्दा है। मुझे यकीन है कि इस मामले पर चर्चा के लिए सरकार और हमारे बीच पूर्ण सहमति होगी। राहुल ने आगे कहा, 'यह कोई वैचारिक मुद्दा नहीं है। इस सदन में मौजूद हर सदस्य इस बात से सहमत होगा कि वायु प्रदूषण और इससे हमारे लोगों को होने वाला नुकसान ऐसी चीज है जिसपर हम सभी मिलकर काम करना चाहेंगे।'

### तमिलनाडु सनातन धर्म के विरोध का प्रतीक बना : अनुराग ठाकुर

लोकसभा में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने तमिलनाडु में दीपक जलाने की मांग करने को लेकर हिंदुओं पर लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया। अनुराग ठाकुर ने तमिलनाडु की डीएमके सरकार पर निशाना साधते हुए कहा-तमिलनाडु सनातन धर्म के विरोध का प्रतीक बन गया है। उनके मंत्री सनातन धर्म के विरुद्ध बयान देते हैं। जब प्रधानमंत्री ने राम मंदिर के लिए अपने कर्तव्य निभाए, तब भी उन्होंने इसका विरोध किया। भाजपा सांसद ने कहा- अभी भी, मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने तिरुप्परनकुंड्रम पहाड़ी पर कार्तिकेय दीपम का दीपक जलाने के अपने आदेश की अनदेखी करने के लिए सरकार की आलोचना की है। अदालत के निर्देशों के बावजूद श्रद्धालुओं पर लाठीचार्ज किया गया। यह स्पष्ट रूप से उल्लंघन और अवमानना है। राज्य में हिंदुओं के साथ इस तरह का भेदभाव क्यों किया जा रहा है? '

### हमने जरूरत पड़ने पर फ्लाइट्स के किराए पर लिमिट लगाई : एविएशन

लोकसभा में विमानों के किराए पर बोलते हुए सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा- महाकुंभ के समय हमने देखा कि पूरे देश और देश के बाहर के लोग प्रयागराज की यात्रा करना चाहते थे। उस समय रूट पर फ्लाइट्स की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई थीं। ऐसे में सरकार ने प्रयागराज जाने वाली सभी फ्लाइट्स के किराए पर लिमिट लगा दी। साथ ही फ्लाइट्स की संख्या भी बढ़ा दी। पहलगाम हमले के बाद भी सरकार ने अपने स्पेशल पावर्स का इस्तेमाल करके ऐसा ही किया था। आगे कहा कि जरूरत पड़ने पर हवाई किराए पर सीमा लगानी होगी, हमने एयरलाइंस को इस बारे में बता दिया है। लेकिन पूरे साल हवाई किराए पर सीमा लगाना संभव नहीं है।

## राहुल की सांसदों के साथ बैठक में नहीं पहुंचे थरूर...कोलकाता में दोस्त की शादी में गए...लगातार तीसरी बार कांग्रेस मीटिंग अटेंड नहीं की...

**नई दिल्ली,12 दिसम्बर 2025।** कांग्रेस सांसद शशि थरूर शुक्रवार को संसद भवन के एनेक्स एक्सटेंशन बिल्डिंग में कांग्रेस सांसदों की बैठक में शामिल नहीं हुए। राहुल गांधी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। इसमें 99 सांसद शामिल हुए थे। बैठक में शीतकालीन सत्र के दौरान अब तक पार्टी के सांसदों के परफॉर्मेंस की समीक्षा की गई। पार्टी सूत्रों के अनुसार, थरूर ने पहले ही पार्टी को अपनी गैरहाजिरी के बारे में जानकारी दे दी थी। थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गुरुवार को बताया था कि वे कोलकाता में अपने एक पुराने दोस्त की शादी में पहुंचे हैं। यह लगातार तीसरी बार है, जब थरूर शीतकालीन सत्र से जुड़ी अहम बैठक में गैरहाजिर रहे। थरूर इससे पहले नवंबर में कांग्रेस की दो बड़ी बैठकों में शामिल नहीं हुए थे। पहली बैठक 30 नवंबर को हुई थी। यह रणनीतिक बैठक सोनिया गांधी ने बुलाई थी।

दूसरी बैठक 18 नवंबर को हुई थी। इसमें एसआईआर प्रक्रिया को लेकर पार्टी की रणनीति पर चर्चा हुई थी।

## सीबीआई ने बड़े साइबर क्राइम नेटवर्क का किया भंडाफोड़,6 आरोपित गिरफ्तार

**नई दिल्ली,12 दिसम्बर 2025।** केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में अमेरिकी नागरिकों से करीब 68 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने वाले अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया। सीबीआई की इस कार्रवाई में अमेरिकी संघीय जांच एजेंसी (एफबीआई) का भी सहयोग रहा। सीबीआई के अनुसार, गिरफ्तार आरोपितों के नाम शुभम सिंह (उर्फ डॉमिनिक), डेल्टानलियन (उर्फ माइकल), जॉर्ज टी जामलियानल (उर्फ माइल्स), एल. सेमिनलें हाओकिप (उर्फ रॉनी), मंगखोलुन (उर्फ मैक्सी) और रॉबर्ट थांगखंखुआल (उर्फ डेविड/मुनरोइन) हैं। ये आरोपित अमेरिकी सरकारी एजेंसियों, जैसे ड्रग एन्फोर्समेंट एजेंसी (डीईए), एफबीआई और सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन (एसएसए) के अधिकारियों के नाम पर कॉल सेंटर चलाकर लोगों को ठगते थे। एजेंसी ने बताया कि इन आरोपितों ने साल 2022 से 2025 तक अमेरिकी नागरिकों को यह धमकी दी कि उनके सोशल सिक्योरिटी नंबर (एसएसएन) का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग डिलीवरी में हुआ है और उनका बैंक खाता फ्रीज कर दिया जाएगा। इसके बाद उन्होंने पीड़ितों को अपने पैसे सुरक्षित करने के लिए 8.5 मिलियन डॉलर को क्रिप्टोकरंसी वॉलेट्स और विदेशी बैंक खातों में ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया। सीबीआई ने 10 और 11 दिसंबर 2025 को दिल्ली, नोएडा और कोलकाता में छापेमारी की। जिसमें 1.88 करोड़ रुपये नकद और 34 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस (मोबाइल फोन, लैपटॉप, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क) सहित कई आपराधिक सबूत बरामद किए गए।

## अन्ना हजारे की चेतावनी के 24 घंटे बाद ही महाराष्ट्र विधान सभा में लोकायुक्त कानून को मिली मंजूरी,मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पेश किया प्रस्ताव

**मुंबई,12 दिसम्बर 2025।** महाराष्ट्र में लोकायुक्त कानून को लेकर समाजसेवी अन्ना हजारे की चेतावनी के एक दिन बाद ही राज्य विधानसभा में बड़ा कदम उठाया गया है। लोकायुक्त कानून, 2023 में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत अब राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आईएएस अधिकारी भी लोकायुक्त की जांच के दायरे में आएंगे। सरकार का कहना है कि यह बदलाव प्रशासनिक पारदर्शिता को मजबूत करेगा और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। विधानसभा में यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पेश किया, जिसे सर्वसम्मति से मंजूरी मिल गई। फडणवीस ने कहा कि संशोधन से यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन-कौन लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में आएंगे और इससे कानून के क्रियान्वयन में अस्पष्टता दूर होगी। उन्होंने बताया कि राज्य के बोर्ड, निगम, समितियों या किसी भी सरकारी संस्था में तैनात वे सभी अधिकारी,जिन्हें सीधे राज्य सरकार ने नियुक्त किया है,अब इस ऐक्ट के तहत जांच के दायरे में शामिल होंगे। हालांकि, सरकार ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि लोकायुक्त कानून को महाराष्ट्र में कब से प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। अन्ना हजारे इसी मुद्दे पर नाराज हैं और उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सरकार जनवरी 2026 से पहले कानून लागू नहीं करती, तो वे आमरण अनशन करेंगे। हजारे का लोकपाल व लोकायुक्त कानून को लागू कराने का संघर्ष नया नहीं है। यूपीए सरकार के दौरान उनके आंदोलन ने देशभर में व्यापक समर्थन हासिल किया था।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2023-2025-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)